V सहकारी बैंक

जमाराशियों और उधार के कारण उच्च ऋण वृद्धि से वर्ष 2024-25 के दौरान शहरी सहकारी बैंकों के तुलन-पत्र में विस्तार हुआ। बेहतर लाभप्रदता, बेहतर आस्ति गुणवत्ता और मजबूत पूंजी बफर के कारण उनका वित्तीय प्रदर्शन मजबूत रहा। इन लाभों को चार-स्तरीय फ्रेमवर्क के तहत आघात-सहनीयता को मजबूत करने के लिए चल रहे समेकन और विनियामक उपायों से सहायता मिली। ग्रामीण सहकारी समितियों ने कृषि ऋण वितरण का समर्थन करना जारी रखा, हालांकि उनका प्रदर्शन अल्पावधिक और दीर्घावधिक संस्थानों में असमान रहा।

परिचय

V.1. सहकारी बैंक भारत की वित्तीय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो अंतिम-छोर तक ऋण का विस्तार करते हैं और स्थानीय वित्तीय मध्यस्थता का समर्थन करते हैं। हाल के वर्षों में, शहरी सहकारी बैंकों में चार-स्तरीय विनियामकीय ढांचे के तहत स्वैच्छिक विलय और विनियामक युक्तिकरण के माध्यम से एक स्थिर समेकन देखा जा रहा है। उन्होंने वर्ष 2024-25 के दौरान तुलन-पत्र का विस्तार दर्ज किया, जो बेहतर ऋण वृद्धि और उच्च जमा जुटाने द्वारा समर्थित है। कम प्रावधानीकरण और उच्च गैर-ब्याज आय के कारण उनकी लाभप्रदता में सुधार हुआ, जबकि पूंजी बफर और आस्ति की गुणवत्ता और मजबूत हुई। ग्रामीण सहकारी समितियों में, अल्पावधिक ऋण संस्थान - जिनमें राज्य और जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां शामिल हैं - कृषि वित्त में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। राज्य सहकारी बैंकों और जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों दोनों ने वर्ष 2024-25 के दौरान आस्ति गुणवत्ता में सुधार के साथ लाभ दर्ज किया। राज्यों में भिन्नता के साथ दीर्घावधिक सहकारी समितियों का प्रदर्शन मिश्रित बना हुआ है।

V.2 इस पृष्ठभूमि में, शेष अध्याय समीक्षाधीन अवधि के दौरान शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों के प्रदर्शन का विश्लेषण करने पर केंद्रित है।[1] खंड 2 में सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की उभरती संरचना को रेखांकित किया गया है, जिसके बाद खंड 3 में शहरी सहकारी बैंकों की लाभप्रदता, आस्ति गुणवत्ता और पूंजी पर्याप्तता का आकलन किया गया है। अल्पावधिक और दीर्घावधिक ग्रामीण सहकारी समितियों के वित्तीय प्रदर्शन की जांच खंड 4 में की गयी है, जिसके बाद खंड 5 में समग्र मूल्यांकन किया गया है।

2. सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की संरचना

V.3. भारत में सहकारी बैंकिंग संरचना में शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) और ग्रामीण ऋण सहकारी समितियां (आरसीसी) शामिल हैं। जबकि यूसीबी मुख्य रूप से शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों की ऋण जरूरतों को पूरा करते हैं, आरसीसी मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए होते हैं। शहरी सहकारी बैंकों को अनुसूचित या गैर-अनुसूचित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जो इस आधार पर है कि (i) क्या वे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल हैं;[2] और (ii) एकल-राज्य या बहु-राज्य उपस्थिति के

[1] प्राथमिक कृषि ऋण समितियां और दीर्घावधिक ग्रामीण ऋण सहकारी समितियां रिज़र्व बैंक के विनियामक दायरे से बाहर हैं। हालांकि, विश्लेषण की पूर्णता के लिए इस अध्याय में उनकी गतिविधियों और प्रदर्शन का एक संक्षिप्त विवरण दिया गया है।

[2] अनुसूचित सहकारी बैंकों के अलावा, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को भी अधिनियम की इसी अनुसूची में शामिल किया गया है।

चार्ट V.1: ऋण सहकारी समितियों की संरचना

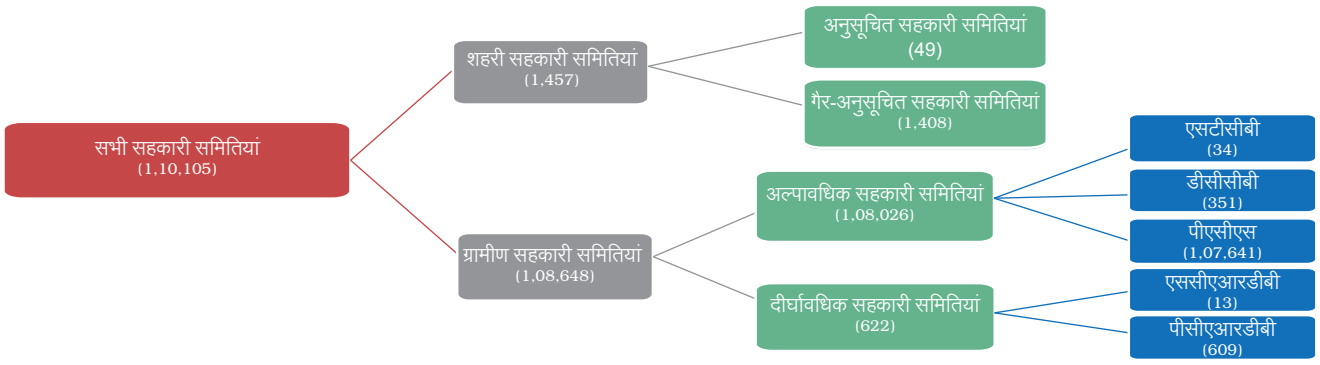

एसटीसीबी: राज्य सहकारी बैंक; डीसीसीबी: जिला सहकारी केंद्रीय बैंक; पीएसीएस: प्राथमिक कृषि ऋण समितियां; एससीएआरडीबी: राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक; पीसीएआरडीबी: प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक।

टिप्पणियाँ: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े मार्च 2025 के अंत में यूसीबी, एसटीसीबी और डीसीसीबी की और मार्च 2024 के अंत में आरसीसी की संख्या दर्शाते हैं।

स्रोत: आरबीआई; राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड); और राज्य सहकारी बैंकों का राष्ट्रीय परिसंघ (एनएएफएससीओबी)।

संदर्भ में उनकी भौगोलिक पहुंच। इसके विपरीत, आरसीसी को अल्पावधिक और दीर्घावधिक संस्थानों में वर्गीकृत किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, 1,457 यूसीबी और 1,08,648 आरसीसी थे (चार्ट V.1)।[3]

V.4. इन संस्थाओं का विनियमन और पर्यवेक्षण एक विभेदित फ्रेमवर्क का पालन करता है। यूसीबी को रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित और पर्यवेक्षित किया जाता है, जबकि राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों (डीसीसीबी) को रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा पर्यवेक्षित किया जाता है। प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस), राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी) और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के दायरे से बाहर हैं।

V.5. मार्च 2024 के अंत में सहकारी क्षेत्र की समेकित आस्तियां ₹24.5 लाख करोड़ थी। आरसीसी में कुल सहकारी क्षेत्र की आस्तियों का 71.2 प्रतिशत शामिल है, जिसमें 68.6 प्रतिशत अल्पावधिक सहकारी समितियों द्वारा और 2.5 प्रतिशत दीर्घावधिक सहकारी समितियों द्वारा है (चार्ट V.2)।

चार्ट V.2: आस्ति के आकार के अनुसार ऋण सहकारी समितियों का विभाजन

(मार्च 2024 के अंत में, प्रतिशत)

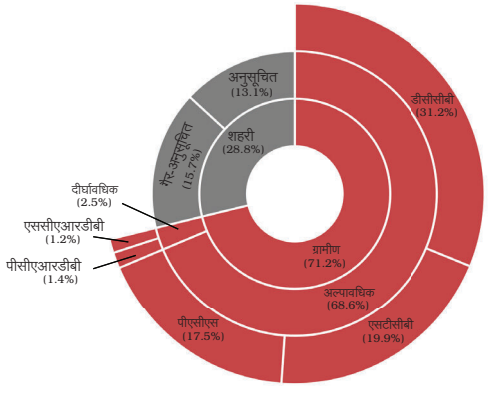

टिप्पणियाँ: 1. सनबर्स्ट चार्ट सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में स्तर को दर्शाता है। चार्ट के प्रत्येक खंड का आकार कुल आस्तियों में उस क्षेत्र की हिस्सेदारी (कोष्ठकों में उल्लिखित) के अनुपात में है।

2. एक दशमलव स्थान तक पूर्णांकित करने के कारण शेयरों की कुल संख्या में अंतर हो सकता है।

स्रोत: आरबीआई, नाबार्ड और एनएएफएससीओबी।

[3] प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस), राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (एससीएआरडीबी) और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (पीसीएआरडीबी) के आंकड़े एक वर्ष के अंतराल के साथ उपलब्ध हैं, यानी वे वर्ष 2023-24 से संबंधित हैं।

3. शहरी सहकारी बैंक

V.6. रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2004-05 में यूसीबी के समेकन की प्रक्रिया शुरू की, जिसमें गैर-अर्थक्षम यूसीबी का उनके व्यवहार्य समकक्षों के साथ विलय, गैर-व्यवहार्य यूसीबी को बंद करना और नए लाइसेंस जारी करना शामिल है। नतीजतन, यूसीबी की संख्या मार्च 2004 के अंत में 1,926 से लगातार घटकर मार्च 2025 के अंत में 1,457 हो गई (चार्ट V.3)।

V.7. वर्ष 2024-25 के दौरान, यूसीबी के सात विलय - छह महाराष्ट्र में और एक तेलंगाना में - प्रभावी हुए। इसके साथ, वर्ष 2004-05 के बाद से विलय की कुल संख्या बढ़कर 163 हो गई, जिनमें से आधे से अधिक महाराष्ट्र में थे (चार्ट V.4ए)। इसके अलावा, वर्ष के दौरान आठ गैर-अनुसूचित यूसीबी के लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे, जिनमें उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में दो-दो और बिहार, महाराष्ट्र, असम और तमिलनाडु में एक-एक शामिल थे। इसके साथ, वर्ष 2020-21 के बाद से लाइसेंस रद्द करने की कुल संख्या बढ़कर 57 हो गई, जो मुख्य रूप से गैर-अनुसूचित श्रेणी में केंद्रित हैं (चार्ट V.4बी)।

चार्ट V.3: शहरी सहकारी बैंकों की संख्या

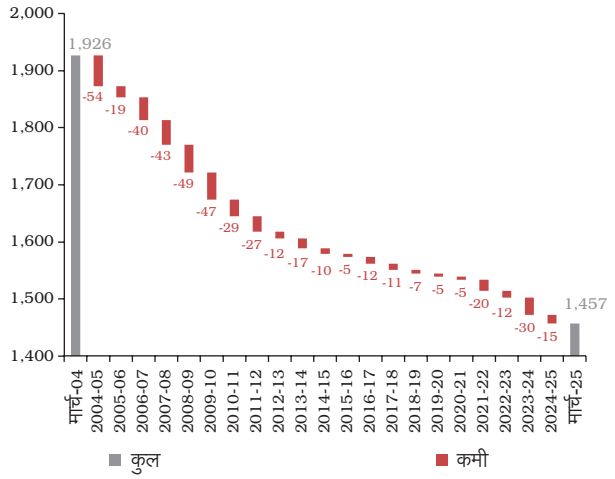

स्रोत: ऑफ-साइट रिटर्न, आरबीआई।

V.8. सहकारी क्षेत्र में विविधता को देखते हुए, रिज़र्व बैंक ने 1 दिसंबर 2022 को यूसीबी पर विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष: श्री एन. एस. विश्वनाथन) की सिफारिशों के अनुरूप यूसीबी के लिए चार-स्तरीय विनियामक फ्रेमवर्क अपनाया।[4] इस विनियमन का उद्देश्य पारस्परिकता और सहयोग की भावना को संतुलित करना है जो भौगोलिक प्रसार और विविध

चार्ट V.4: शहरी सहकारी बैंकों में समेकन अभियान

ए. विलय का भौगोलिक विभाजन
(वर्ष 2004-05 से 2024-25 के दौरान विलय की संख्या)

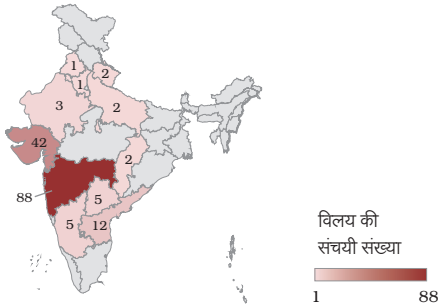

बी. लाइसेंस निरसन की संख्या

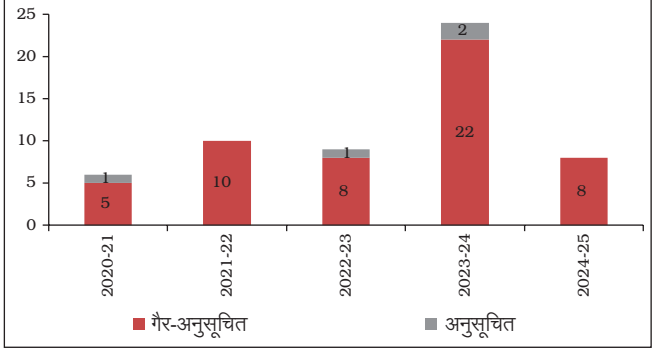

टिप्पणी: शिमशा सहकारा बैंक नियमिता, कर्नाटक का लाइसेंस 5 जुलाई 2024 की प्रेस विज्ञप्ति में अधिसूचित किया गया था। इसके बाद, बैंक ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में रिट याचिका (डब्ल्यूपी संख्या 19767/2024) दायर की, जिसमें न्यायालय ने 25 जुलाई 2024 के अंतरिम आदेश द्वारा 5 जुलाई 2024 के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी। बैंक वर्तमान में आरबीआई की 8 अगस्त 2024 की प्रेस विज्ञप्ति में अधिसूचित व्यापक निर्देशों के अधीन है।
स्रोत: आरबीआई।

[4] ₹100 करोड़ तक की जमा राशि वाले यूसीबी को टियर 1 के रूप में वर्गीकृत किया गया है; टियर 2 के रूप में ₹100 करोड़ से अधिक और ₹1,000 करोड़ तक की जमा राशि वाले; टियर 3 के रूप में ₹1,000 करोड़ से अधिक और ₹10,000 करोड़ तक की जमा राशि वाले; और ₹10,000 करोड़ से अधिक को टियर 4 में रखा गया है। 01 दिसंबर 2022 के परिपत्र के अनुसार, सभी यूसीबी इकाइयों और वेतनभोगियों के यूसीबी (जमा आकार के बगैर) को टियर 1 यूसीबी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उपर्युक्त जमाराशियों की गणना पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार की जाएगी।

सारणी V.1: शहरी सहकारी बैंकों का टियर-वार वितरण
(मार्च 2025 के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में, प्रतिशत में शेयर)

टियर का प्रकार	बैंकों की संख्या		जमाराशियाँ		अग्रिम		कुल आस्तियां	
	संख्या	शेयर	संख्या	शेयर	संख्या	शेयर	संख्या	शेयर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	838	57.5	65,760	11.3	43,991	11.9	89,089	12.1
2	535	36.7	1,78,433	30.5	1,09,980	29.7	2,24,705	30.4
3	78	5.4	2,01,311	34.4	1,22,712	33.1	2,48,549	33.6
4	6	0.4	1,38,910	23.8	93,542	25.3	1,76,386	23.9
सभी यूसीबी	**1,457**	**100.0**	**5,84,415**	**100.0**	**3,70,225**	**100.0**	**7,38,729**	**100.0**

टिप्पणियाँ: 1. डेटा अंतरिम है।
2. पूर्णांकन के कारण घटकों का योग कुल योग के बराबर नहीं हो सकता है।

स्रोत: ऑफ-साइट रिटर्न, आरबीआई।

व्यावसायिक गतिविधियों वाले बड़े आकार के यूसीबी की विकास महत्वाकांक्षाओं की तुलना में परिचालन के सीमित क्षेत्र वाले छोटे बैंकों में अधिक प्रचलित है। मार्च 2025 के अंत में, 57.5 प्रतिशत यूसीबी को टियर 1 के रूप में वर्गीकृत किया गया था। टियर 3 और टियर 4 यूसीबी, यूसीबी की कुल संख्या में 6 प्रतिशत से कम हिस्सेदारी के साथ, इस क्षेत्र पर हावी थे, जिनके पास जमा, अग्रिम और कुल आस्तियों के आधे से अधिक हिस्से थे (सारणी V.1)।

3.1. तुलन पत्र

V.9. वर्ष 2024-25 के दौरान यूसीबी के समेकित तुलन पत्र में 4.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष के 4.0 प्रतिशत से मामूली रूप से अधिक है (सारणी V.2)। यूसीबी

सारणी V.2: शहरी सहकारी बैंकों के तुलन पत्र
(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

मदें	अनुसूचित यूसीबी		गैर-अनुसूचित यूसीबी		सभी यूसीबी		सभी यूसीबी में वृद्धि (%)	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2023-24	2024-25
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1) पूंजी	4,293 (1.3)	4,271 (1.3)	10,828 (2.8)	11,217 (2.8)	15,120 (2.1)	15,489 (2.1)	2.8	2.4
2) आरक्षित निधि और अधिशेष	25,290 (7.9)	27,029 (8.0)	29,383 (7.6)	32,276 (8.1)	54,673 (7.7)	59,305 (8.0)	13.3	8.5
3) जमाराशियाँ	2,54,479 (79.1)	2,70,209 (79.7)	3,00,931 (78.0)	3,14,207 (78.6)	5,55,410 (78.5)	5,84,415 (79.1)	4.1	5.2
4) उधार	5,082 (1.6)	5,534 (1.6)	293 (0.1)	243 (0.1)	5,375 (0.8)	5,776 (0.8)	-13.9	7.5
5) अन्य देयताएं और प्रावधान	32,579 (10.1)	32,158 (9.5)	44,382 (11.5)	41,586 (10.4)	76,961 (10.9)	73,744 (10.0)	-0.7	-4.2
कुल देयताएँ/आस्तियां	**3,21,723 (100.0)**	**3,39,200 (100.0)**	**3,85,816 (100.0)**	**3,99,529 (100.0)**	**7,07,539 (100.0)**	**7,38,729 (100.0)**	**4.0**	**4.4**
1) हाथ में नकद	1,759 (0.5)	1,764 (0.5)	4,424 (1.1)	4,194 (1.0)	6,183 (0.9)	5,958 (0.8)	5.1	-3.6
2) आरबीआई के पास शेष राशि	13,778 (4.3)	13,687 (4.0)	4,544 (1.2)	4,688 (1.2)	18,322 (2.6)	18,375 (2.5)	12.0	0.3
3) बैंकों के पास शेष राशि	24,701 (7.7)	30,263 (8.9)	47,756 (12.4)	50,374 (12.6)	72,457 (10.2)	80,637 (10.9)	8.6	11.3
4) कॉल और अल्प सूचना पर मुद्रा	2,367 (0.7)	2,908 (0.9)	1,033 (0.3)	1,370 (0.3)	3,401 (0.5)	4,278 (0.6)	-1.1	25.8
5) निवेश	86,626 (26.9)	86,619 (25.5)	1,07,018 (27.7)	1,06,851 (26.7)	1,93,644 (27.4)	1,93,471 (26.2)	1.6	-0.1
6) ऋण और अग्रिम	1,59,553 (49.6)	1,71,391 (50.5)	1,87,300 (48.5)	1,98,833 (49.8)	3,46,853 (49.0)	3,70,225 (50.1)	5.0	6.7
7) अन्य आस्तियां	32,939 (10.2)	32,568 (9.6)	33,741 (8.7)	33,218 (8.3)	66,679 (9.4)	65,786 (8.9)	0.1	-1.3

टिप्पणियाँ 1. वर्ष 2025 के आंकड़े अनंतिम हैं।
2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं/आस्तियों के अनुपात (प्रतिशत में) दर्शाते हैं।
3. पूर्णांकन के कारण घटकों का योग कुल योग के बराबर नहीं हो सकता है।

स्रोत: ऑफ-साइट रिटर्न, आरबीआई।

चार्ट V.5: आस्ति में वृद्धि

(व-द-व, प्रतिशत)

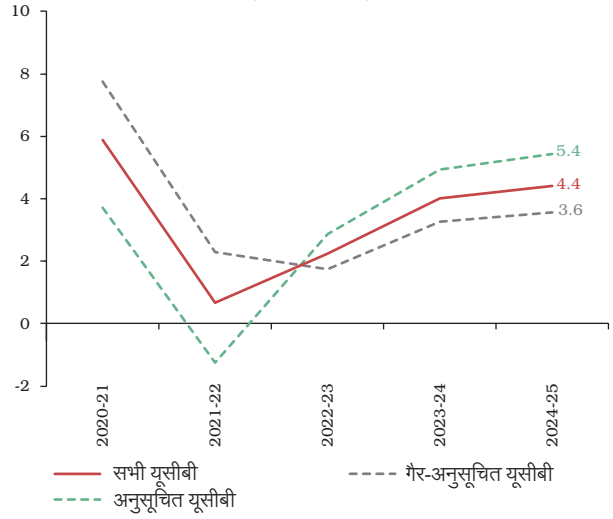

टिप्पणी : वर्ष 2025 के डेटा अनंतिम हैं।
स्रोत: ऑफ-साइट रिर्टन, आरबीआई।

चार्ट V.7: यूसीबी के ऋण-जमा अनुपात

(मार्च के अंत में, प्रतिशत)

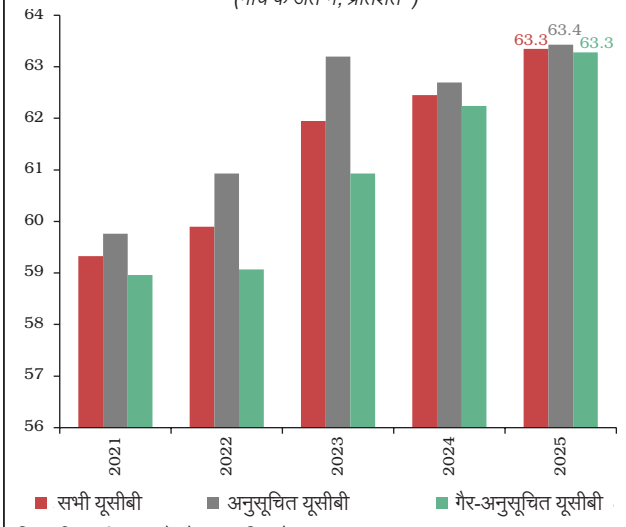

टिप्पणी : वर्ष 2025 के डेटा अनंतिम हैं।
स्रोत: ऑफ-साइट रिर्टन, आरबीआई।

में, गैर-अनुसूचित यूसीबी (3.6 प्रतिशत) की तुलना में अनुसूचित यूसीबी (5.4 प्रतिशत) के लिए वृद्धि अधिक रही (चार्ट V.5)।

V.10. यूसीबी की जमा वृद्धि वर्ष 2024-25 के दौरान 4.1 प्रतिशत से बढ़कर 5.2 प्रतिशत हो गई (चार्ट V.6ए)। यूसीबी की ऋण वृद्धि भी बढ़कर 6.7 प्रतिशत हो गई, जो पिछले छह वर्षों में सबसे अधिक है, और अनुसूचित और गैर-अनुसूचित दोनों प्रकार के यूसीबी में सुधार देखा गया (चार्ट V.6बी)। सितंबर 2025 के अंत में, यूसीबी की जमा वृद्धि और ऋण वृद्धि क्रमशः 6.8 प्रतिशत और 6.4 प्रतिशत थी।

V.11. जमा वृद्धि के सापेक्ष उच्च ऋण वृद्धि के कारण, यूसीबी का ऋण-जमा (सीडी) अनुपात मार्च 2025 के अंत में 63.3 प्रतिशत हो गया, जो मार्च 2024 के अंत में 62.4 प्रतिशत था (चार्ट V.7)।

चार्ट V.6: जमा और अग्रिम

ए. जमा वृद्धि

(व-द-व, प्रतिशत)

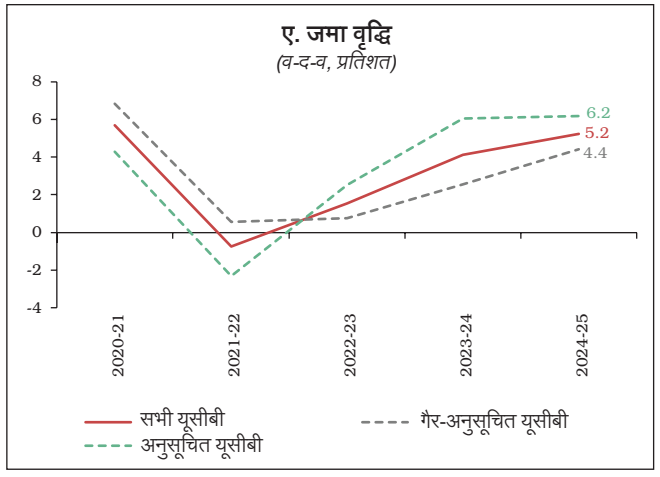

बी. ऋण वृद्धि

(व-द-व, प्रतिशत)

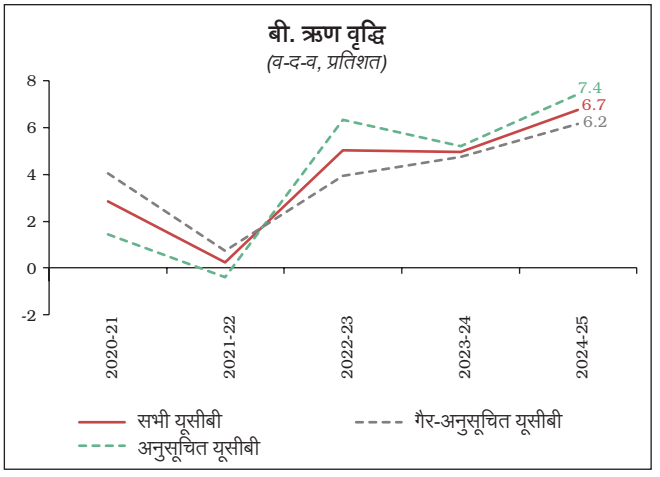

टिप्पणी : वर्ष 2025 के डेटा अनंतिम हैं।
स्रोत: ऑफ-साइट रिर्टन, आरबीआई।

V.12. यूसीबी मुख्य रूप से फंडिंग के लिए जमा पर निर्भर करते हैं, जो मार्च 2025 के अंत में उधार के साथ कुल देयताओं का केवल 0.8 प्रतिशत है। वर्ष 2024-25 के दौरान, यूसीबी की निवेश वृद्धि लगातार चौथे वर्ष कम रही और ऋणात्मक हो गई, जो आंशिक रूप से निवेश से ऋण और अग्रिम में धन को पुनः आवंटित करने की उनकी कार्यनीति को दर्शाती है (चार्ट V.8)।

V.13. पिछले एक दशक में, औसतन, एसएलआर निवेश यूसीबी के कुल निवेश का लगभग 89 प्रतिशत था। हालांकि, एसएलआर निवेश की संरचना राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की ओर बढ़ रही है, मार्च 2015 के अंत में उनकी हिस्सेदारी 15.2 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2025 के अंत में 36.8 प्रतिशत हो गई है (सारणी V.3 और चार्ट V.9)।

V.14. मार्च 2025 के अंत में, 46.3 प्रतिशत यूसीबी के पास ₹50 करोड़ से कम अग्रिम थे, जबकि सबसे बड़े 57 यूसीबी के पास यूसीबी के कुल अग्रिमों का 53.9 प्रतिशत था। आस्तियों के संदर्भ में, 23.9 प्रतिशत यूसीबी की आस्तियों का आकार ₹50 करोड़ से कम था, जबकि ₹1000 करोड़ से अधिक की आस्तियों वाले यूसीबी की कुल आस्तियों का 65.5 प्रतिशत हिस्सा थे (सारणी V.4)। जमा राशि के मामले में भी ऐसा ही पैटर्न देखने को मिला, जिसमें जमा राशि का संकेंद्रण बड़े आकार के बैंकों में जारी रहा। बड़े यूसीबी की बढ़ती हिस्सेदारी इस क्षेत्र में चल रहे समेकन और विस्तार को दर्शाती है।

सारणी V.3: शहरी सहकारी बैंकों द्वारा निवेश

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	बकाया राशि (मार्च के अंत में)		घट-बढ़ (प्रतिशत में)	
	2024	2025	2023-24	2024-25
1	2	3	4	5
कुल निवेश (ए + बी)	1,93,644 (100.0)	1,93,471 (100.0)	1.6	-0.1
ए. एसएलआर निवेश (i+ii+iii)	1,74,332 (90.0)	1,72,799 (89.3)	1.5	-0.9
(i) केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां	1,06,270 (54.9)	99,916 (51.6)	-0.4	-6.0
(ii) राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	67,673 (34.9)	71,213 (36.8)	4.6	5.2
(iii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	389 (0.2)	1,670 (0.9)	27.9	329.5
बी. गैर-एसएलआर निवेश	19,312 (10.0)	20,672 (10.7)	1.9	7.0

टिप्पणियाँ: 1. वर्ष 2025 के लिए डेटा अनंतिम हैं।
2. कोष्ठक में आंकड़े कुल निवेश (प्रतिशत में) का अनुपात हैं।
3. पूर्णांकन के कारण घटकों का योग पूर्ण नहीं हो सकता है।

स्रोत: ऑफ-साइट रिटर्न, आरबीआई।

चार्ट V.8 : निवेश वृद्धि

(व-द-व, प्रतिशत)

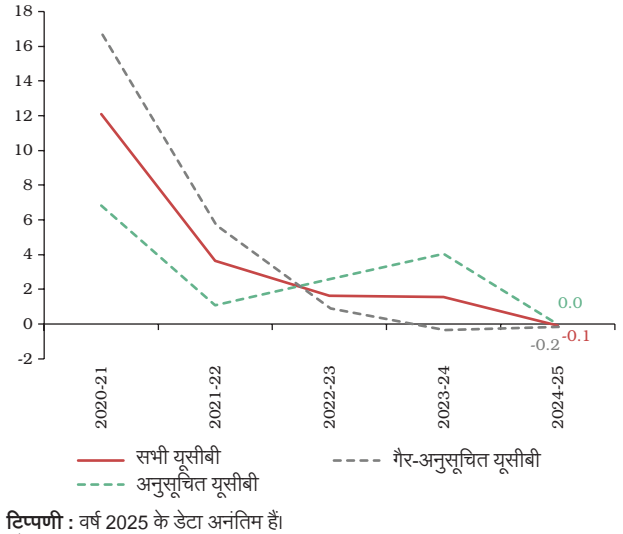

टिप्पणी : वर्ष 2025 के डेटा अनंतिम हैं।
स्रोत: ऑफ-साइट रिर्टन, आरबीआई।

चार्ट V.9: यूसीबी के निवेश का संघटन

(मार्च के अंत में, प्रतिशत में शेयर)

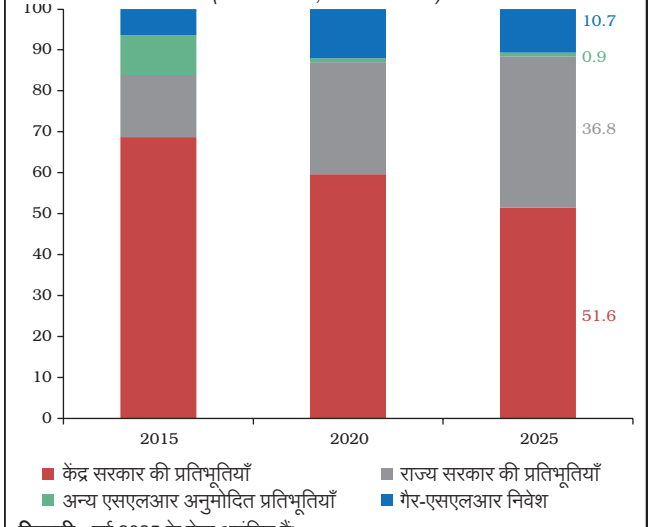

टिप्पणी : वर्ष 2025 के डेटा अनंतिम हैं।
स्रोत: ऑफ-साइट रिर्टन, आरबीआई।

सारणी V.4: जमा, अग्रिमों और आस्तियों के आकार के आधार पर यूसीबी का विभाजन
(मार्च 2025 के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	जमा		अग्रिम		आस्ति	
	यूसीबी की संख्या	राशि	यूसीबी की संख्या	राशि	यूसीबी की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7
0 ≤ X < 10	76	426	161	894	43	250
10 ≤ X < 25	158	2,772	240	4,024	107	1,901
25 ≤ X < 50	236	8,741	273	9,777	198	7,201
50 ≤ X < 100	289	20,811	253	17,978	297	21,542
100 ≤ X < 250	320	52,010	267	41,517	360	58,874
250 ≤ X < 500	167	59,779	137	48,504	193	68,858
500 ≤ X < 1000	109	74,624	69	48,066	136	96,262
1000 ≤ X	102	3,65,252	57	1,99,464	123	4,83,841
कुल	**1,457**	**5,84,415**	**1,457**	**3,70,225**	**1,457**	**7,38,729**

टिप्पणियाँ: 1. डेटा अनंतिम हैं।
2. 'X' जमा, अग्रिम और आस्तियों की मात्रा को इंगित करता है।
स्रोत: ऑफ-साइट रिटर्न, आरबीआई।

3.2. वित्तीय प्रदर्शन और लाभप्रदता

V.15. हालांकि घटकों में भिन्नता के साथ वर्ष 2024-25 के दौरान यूसीबी के वित्तीय प्रदर्शन में सुधार हुआ। गैर-अनुसूचित यूसीबी के परिचालन लाभ में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो गैर-ब्याज आय में तेज वृद्धि से प्रेरित है।[5] इसके विपरीत, अनुसूचित यूसीबी के परिचालन लाभ में 5.5 प्रतिशत की कमी आई, जो कुल आय के सापेक्ष कुल व्यय में तेजी से वृद्धि को दर्शाता है (सारणी V.5 और परिशिष्ट सारणी V.1)।

V.16. कुल मिलाकर, वर्ष 2024-25 में कर पश्चात यूसीबी का निवल लाभ 14.2 प्रतिशत बढ़ा, जो वर्ष 2023-24 में दर्ज की गई 52 प्रतिशत की वृद्धि के शीर्ष पर है, जो बेहतर आस्ति गुणवत्ता के कारण कम प्रावधानीकरण दबाव के कारण भी है। लाभप्रदता में सुधार आस्तियों पर उच्च प्रतिलाभ (आरओए) और इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) में भी स्पष्ट था। तथापि, ब्याज आय की तुलना में ब्याज व्यय में तीव्र वृद्धि के कारण यूसीबी का निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) कम हो गया है (सारणी V.6)। यूसीबी में, गैर-अनुसूचित यूसीबी के एनआईएम और आरओए अनुसूचित यूसीबी से अधिक थे (सारणी V.10ए

सारणी V.5: अनुसूचित और गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	अनुसूचित यूसीबी		गैर-अनुसूचित यूसीबी		सभी यूसीबी		सभी यूसीबी (व-द-व वृद्धि प्रतिशत में)	
	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ए. कुल आय [i+ii]	**24,161 (100.0)**	**26,059 (100.0)**	**31,036 (100.0)**	**33,293 (100.0)**	**55,198 (100.0)**	**59,352 (100.0)**	**5.4**	**7.5**
i. ब्याज आय	21,476 (88.9)	23,065 (88.5)	29,223 (94.2)	30,296 (91.0)	50,698 (91.8)	53,361 (89.9)	6.5	5.3
ii. गैर-ब्याज आय	2,686 (11.1)	2,993 (11.5)	1,814 (5.8)	2,997 (9.0)	4,499 (8.2)	5,990 (10.1)	-5.9	33.1
बी. कुल व्यय [i+ii]	**19,785 (100.0)**	**21,925 (100.0)**	**25,985 (100.0)**	**27,819 (100.0)**	**45,771 (100.0)**	**49,745 (100.0)**	**7.9**	**8.7**
i. ब्याज व्यय	12,838 (64.9)	14,542 (66.3)	17,444 (67.1)	18,850 (67.8)	30,282 (66.2)	33,392 (67.1)	10.2	10.3
ii. गैर-ब्याज व्यय	6,947 (35.1)	7,383 (33.7)	8,541 (32.9)	8,969 (32.2)	15,488 (33.8)	16,352 (32.9)	3.7	5.6
जिनमें से: स्टाफ व्यय	2,999	3,288	4,367	4,785	7,365	8,073	2.1	9.6
सी. लाभ								
i. परिचालन लाभ की राशि	4,376	4,133	5,051	5,474	9,427	9,607	-5.4	1.9
ii. प्रावधान और आकस्मिकताएँ	1,214	1,154	1,912	1,568	3,127	2,722	-43.9	-12.9
iii. करों के लिए प्रावधान	752	737	868	803	1,620	1,540	22.8	-4.9
iv. करों से पहले निवल लाभ की राशि	3,162	2,980	3,139	3,905	6,300	6,885	43.2	9.3
v. करों के बाद निवल लाभ की राशि	2,410	2,243	2,270	3,102	4,680	5,345	52.0	14.2

टिप्पणियाँ: 1. वर्ष 2024-25 के आंकड़े अनंतिम हैं।
2. कोष्ठक में आंकड़े कुल आय/व्यय (प्रतिशत में) का अनुपात हैं।
3. पूर्णांकन के कारण घटकों का योग पूर्ण नहीं हो सकता है।
स्रोत: ऑफ-साइट रिटर्न, आरबीआई।

[5] गैर-ब्याज आय में वृद्धि विविध आय में वृद्धि, अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ और प्रतिभूतियों के व्यापार और बिक्री पर लाभ से प्रेरित है।

सारणी V.6 : यूसीबी के चुनिंदा लाभप्रदता संकेतक

(प्रतिशत)

मद	अनुसूचित यूसीबी		गैर-अनुसूचित यूसीबी		सभी यूसीबी	
	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25
1	2	3	4	5	6	7
आस्तियों पर प्रतिलाभ	0.77	0.68	0.63	0.79	0.70	0.74
इक्विटि पर प्रतिलाभ	8.54	7.37	6.18	7.40	7.18	7.39
निवल ब्याज मार्जिन	3.60	3.38	4.08	3.83	3.86	3.62

टिप्पणी: वर्ष 2024-25 के लिए डेटा अनंतिम हैं।
स्रोत: ऑफ-साइट रिटर्न, आरबीआई।

सारणी V.7: सीआरएआर-वार यूसीबी का विभाजन
(मार्च 2025 के अंत में)

(बैंकों की संख्या)

सीआरएआर (प्रतिशत में)	अनुसूचित यूसीबी	गैर-अनुसूचित यूसीबी	सभी यूसीबी
1	2	3	4
सीआरएआर < 3	1	28	29
3 <= सीआरएआर < 6	2	8	10
6 <= सीआरएआर < 9	0	10	10
9 <= सीआरएआर < 12	0	66	66
12 <= सीआरएआर	46	1,296	1,342
कुल	**49**	**1,408**	**1,457**

टिप्पणी: डेटा अनंतिम है।
स्रोत: ऑफ-साइट रिटर्न, आरबीआई।

और बी)। वर्ष 2025-26 की पहली छमाही के दौरान, यूसीबी का आरओए और आरओई क्रमशः 0.8 प्रतिशत और 8.2 प्रतिशत रहा।

3.3. दंड और डीआईसीजीसी दावे

V.17. वर्ष 2024-25 के दौरान सहकारी बैंकों (यूसीबी सहित) पर जुर्माना लगाने के मामलों की संख्या 22.8 प्रतिशत बढ़कर 264 हो गई। लगाए गए जुर्माने की कुल राशि भी वर्ष 2024-25 के दौरान बढ़कर ₹15.6 करोड़ हो गई, जो पिछले वर्ष में ₹12.1 करोड़ थी (अध्याय IV में सारणी IV.15) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) ने वर्ष 2024-25 के दौरान ₹476 करोड़ के दावों का निपटान किया, जो पूरी तरह से रिज़र्व बैंक के परिसमापन/सर्व-समावेशी निर्देशों (एआईडी) के तहत रखे गए सहकारी बैंकों से संबंधित था।

3.4. पूंजी पर्याप्तता

V.18. 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी संशोधित विनियामकीय फ्रेमवर्क के अनुसार, टियर 1 यूसीबी के लिए 9 प्रतिशत और टियर 2 से 4 यूसीबी के लिए 12 प्रतिशत की न्यूनतम पूंजी और जोखिम-भारित आस्तियों के अनुपात (सीआरएआर) को निरंतर आधार पर बनाए रखा जाना है। मार्च 2025 के अंत में, 92.1 प्रतिशत यूसीबी ने सीआरएआर को 12 प्रतिशत से ऊपर बनाए रखा (सारणी V.7 और परिशिष्ट सारणी V.2)।

चार्ट V.10: लाभप्रदता संकेतक

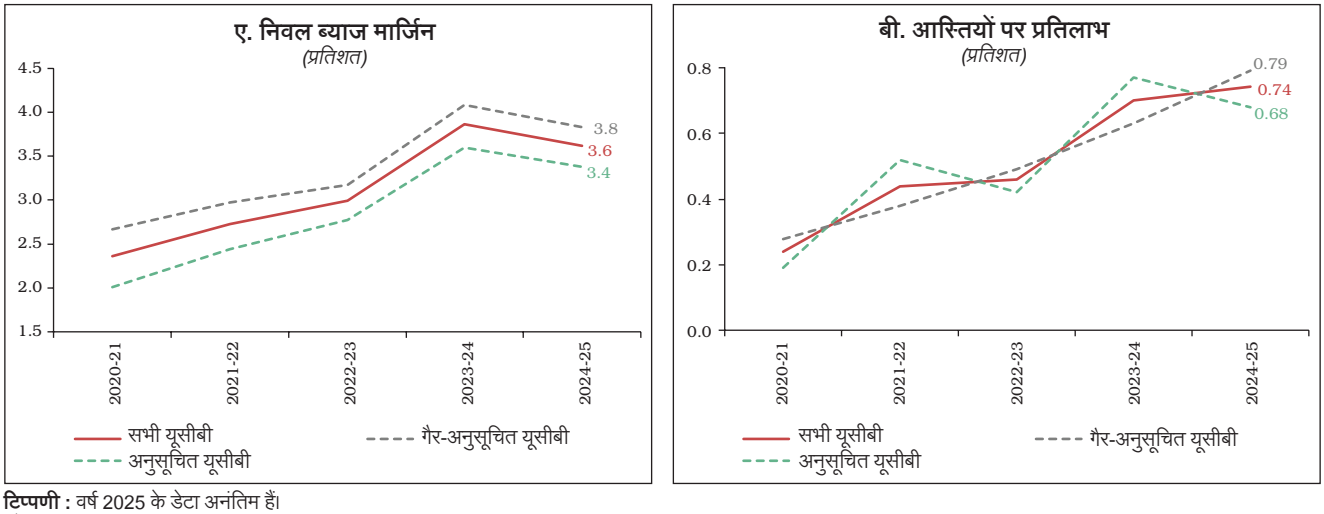

टिप्पणी : वर्ष 2025 के डेटा अनंतिम हैं।
स्रोत: ऑफ-साइट रिर्टन, आरबीआई।

सारणी V.8: यूसीबी की घटक-वार पूंजी पर्याप्तता
(मार्च के अंत में)

(राशि स्करोड़ में)

मद	अनुसूचित यूसीबी		गैर-अनुसूचित यूसीबी		सभी यूसीबी	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1. पूंजीगत निधि	**25,966**	**28,320**	**32,560**	**36,782**	**58,526**	**65,101**
i) टियर 1 पूंजी	20,128	21,960	28,423	32,401	48,550	54,362
ii) टियर 2 पूंजी	5,838	6,359	4,138	4,380	9,976	10,740
2. जोखिम-भारित आस्तियां	**1,57,720**	**1,69,923**	**1,78,224**	**1,91,098**	**3,35,944**	**3,61,022**
3. सीआरएआर (2 के % के रूप में 1)	**16.5**	**16.7**	**18.3**	**19.2**	**17.4**	**18.0**
जिनमें से:						
टियर 1	12.8	12.9	15.9	17.0	14.5	15.1
टियर 2	3.7	3.7	2.3	2.3	3.0	3.0

टिप्पणियाँ : 1. मार्च अंत 2025 का डेटा अनंतिम है।
2. पूर्णांकन के कारण घटकों का योग पूर्ण नहीं हो सकता है।
स्रोत: ऑफ-साइट रिटर्न, आरबीआई।

V.19. वर्ष 2024-25 के दौरान, यूसीबी अच्छी तरह से पूंजीकृत रहे, मुख्य रूप से टियर 1 पूंजी अनुपात में सुधार के कारण सीआरएआर एक वर्ष पहले के 17.4 प्रतिशत से बढ़कर 18.0 प्रतिशत हो गया (सारणी V.8 और चार्ट V.11ए)। यूसीबी में गैर-अनुसूचित यूसीबी ने अनुसूचित यूसीबी की तुलना में उच्च सीआरएआर बनाए रखा (चार्ट V.11बी)। सितंबर 2025 के अंत में सीआरएआर 18.0 प्रतिशत पर स्थिर रहा।

3.5. आस्ति गुणवत्ता

V.20. सकल अनर्जक आस्ति (जीएनपीए) अनुपात द्वारा मापी जाने वाली यूसीबी की आस्ति गुणवत्ता में लगातार चौथे वर्ष सुधार हुआ, जिसमें मार्च 2025 के अंत में जीएनपीए अनुपात 6.2 प्रतिशत था, जो मार्च 2021 के अंत में 12.1 प्रतिशत के शिखर से नीचे था (चार्ट V.12)। सितंबर 2025 के अंत में, यूसीबी का जीएनपीए अनुपात एक वर्ष पहले 9.3 प्रतिशत की तुलना में 7.6 प्रतिशत रहा।

V.21. अनुसूचित और गैर-अनुसूचित यूसीबी में जीएनपीए अनुपात में कमी के साथ आस्ति गुणवत्ता में सुधार व्यापक आधार पर हुआ है। जीएनपीए में गिरावट के साथ, यूसीबी का प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) बढ़कर 90.1 प्रतिशत हो गया। यह सुधार आंशिक रूप से मानक अग्रिमों के लिए

चार्ट V.11: पूंजी और जोखिम-भारित आस्तियों का अनुपात
(मार्च के अंत में)

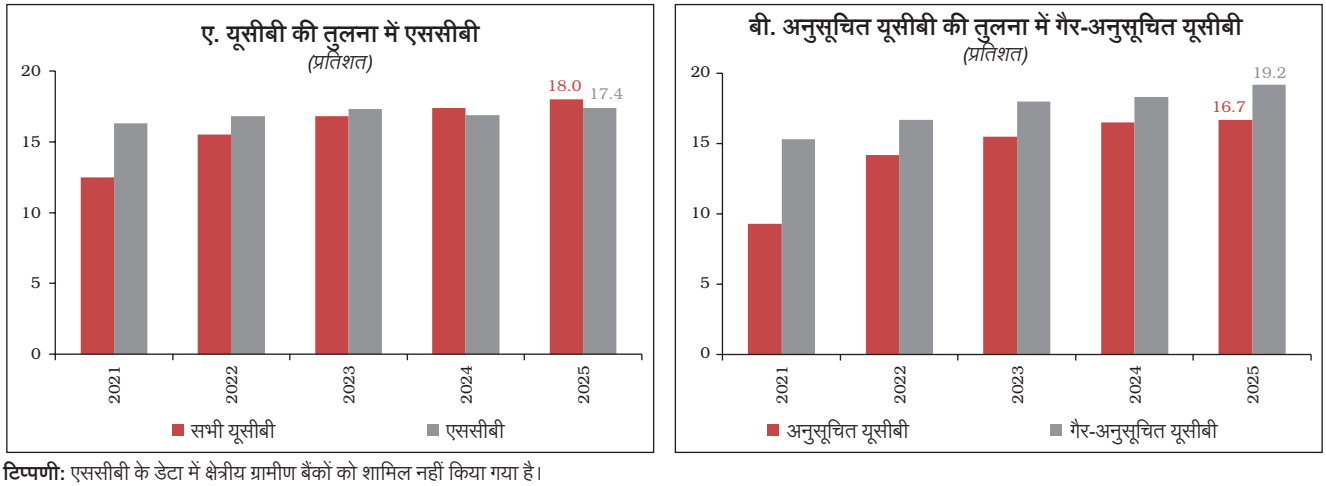

टिप्पणी: एससीबी के डेटा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को शामिल नहीं किया गया है।
स्रोत: ऑफ-साइट रिटर्न, आरबीआई; और संबंधित बैंकों के वार्षिक लेखे।

चार्ट V.12: प्रावधानीकरण और आस्ति गुणवत्ता

(मार्च के अंत में, प्रतिशत, बायां मान; मार्च के अंत में, प्रतिशत, दायां मान)

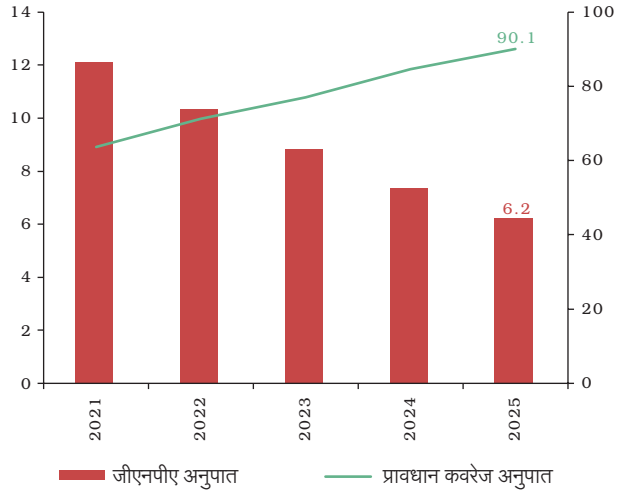

टिप्पणी : वर्ष 2025 के डेटा अनंतिम हैं।
स्रोत: ऑफ-साइट रिर्टन, आरबीआई।

यूसीबी के प्रावधान मानदंडों के सामंजस्य के कारण था।[6] यूसीबी का निवल एनपीए अनुपात मार्च 2025 के अंत में गिरकर 0.7 प्रतिशत हो गया, जो एक वर्ष पहले 1.2 प्रतिशत था (सारणी V.9)।

V.22. ₹5 करोड़ या उससे अधिक के ऋण वाले खातों के रूप में परिभाषित बड़े उधार खातों में यूसीबी का ऋण वर्ष 2024-25 के दौरान कम हुआ। मार्च 2025 के अंत तक यूसीबी के कुल ऋण में इसका हिस्सा घटकर 23.4 प्रतिशत रह गया, हालांकि अनुसूचित यूसीबी का अनुपात (40.9 प्रतिशत) गैर-अनुसूचित यूसीबी (8.2 प्रतिशत) की तुलना में अधिक है। बड़े उधार खातों का यूसीबी के कुल जीएनपीए में लगभग एक तिहाई योगदान रहा, जिसमें अनुसूचित यूसीबी (64.8 प्रतिशत) और गैर-अनुसूचित यूसीबी (16.6 प्रतिशत) के बीच व्यापक अंतर देखा गया। पूरे क्षेत्र के लिए, विशेष उल्लेख खाते-1 (एसएमए-1) में वर्ष के दौरान गिरावट आई, जबकि एसएमए-0 खातों में वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से अनुसूचित यूसीबी द्वारा संचालित था (चार्ट V.13)।

सारणी V.9: यूसीबी की अनर्जक आस्तियां
(मार्च 2025 के अंत में)

मद	अनुसूचित यूसीबी		गैर-अनुसूचित यूसीबी		सभी यूसीबी	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
सकल एनपीए (₹ करोड़)	8,422	8,015	16,973	15,057	25,395	23,072
सकल एनपीए अनुपात (प्रतिशत)	5.3	4.7	9.1	7.6	7.3	6.2
निवल एनपीए (₹ करोड़)	1,960	1,561	1,954	711	3,914	2,273
निवल एनपीए अनुपात (प्रतिशत)	1.3	0.9	1.1	0.4	1.2	0.7
प्रावधानीकरण (₹ करोड़)	6,462	6,454	15,019	14,346	21,481	20,800
प्रावधान कवरेज अनुपात (प्रतिशत)	76.7	80.5	88.5	95.3	84.6	90.1

टिप्पणी : वर्ष 2025 का डेटा अनंतिम है।
स्रोत: ऑफ-साइट रिटर्न, आरबीआई।

3.6. *प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण*

V.23. मार्च 2025 के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) दिशानिर्देशों के अनुसार, रिज़र्व बैंक ने यूसीबी के लिए समग्र पीएसएल लक्ष्य को संशोधित किया, जो कि निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के 60 प्रतिशत या तुलनपत्र बाह्य एक्स्पोज़र के समतुल्य ऋण (सीईओबीएसई) की ऋण-समतुल्य राशि जो भी

चार्ट V.13: बड़े उधार खातों में दबाव

(मार्च के अंत में, वित्त पोषित राशि का प्रतिशत)

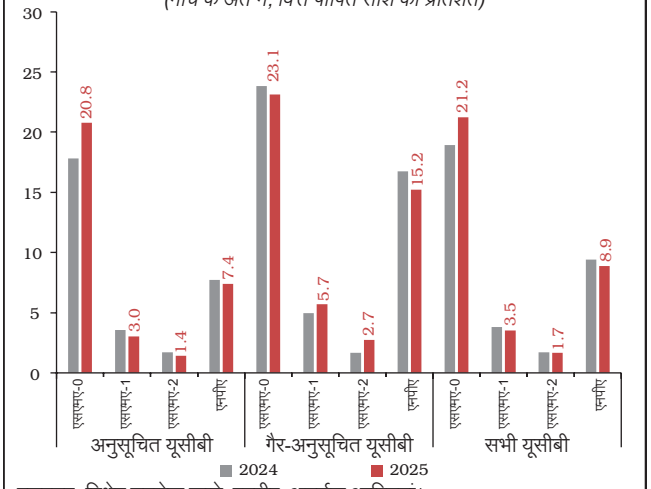

एसएमए: विशेष उल्लेख खाते; एनपीए: अनर्जक आस्तियां।
टिप्पणी: बड़े उधार खातों को 5 करोड़ रुपये और उससे अधिक के एक्सपोजर वाले खातों के रूप में परिभाषित किया गया है।
स्रोत: ऑफ-साइट रिटर्न, आरबीआई।

[6] पूर्ववर्ती टियर 1 यूसीबी, जो 'उपरोक्त में शामिल नहीं किए गए अन्य सभी ऋणों और अग्रिमों' पर 0.25 प्रतिशत का मानक आस्ति प्रावधान बनाए रख रहे थे, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से प्रावधान की आवश्यकता को बढ़ाकर 31 मार्च 2024 तक 0.30 प्रतिशत; 30 सितंबर 2024 तक 0.35 प्रतिशत; और 31 मार्च 2025 तक 0.40 प्रतिशत तक पहुंचने की आवश्यकता थी।

चार्ट V.14: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार-लक्ष्य और उपलब्धियां

(प्रतिशत)

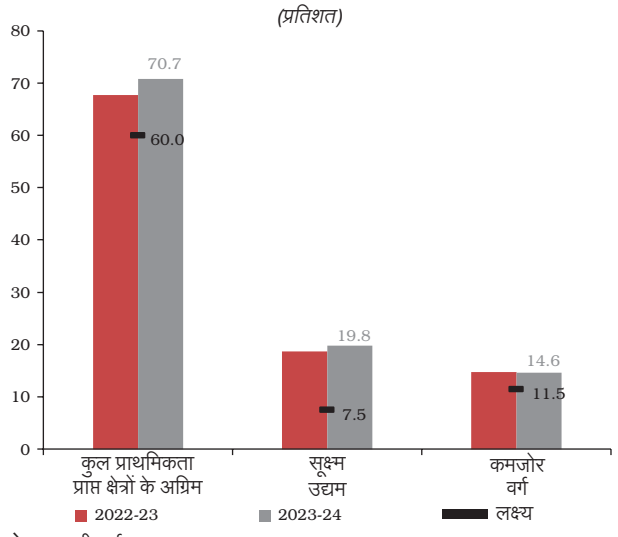

स्रोत: आरबीआई।

अधिक हो, इसे वर्ष 2024-25 से प्रभावी किया जाएगा।[7] वर्ष 2023-24 के दौरान, यूसीबी ने 60 प्रतिशत के समग्र पीएसएल लक्ष्य के साथ-साथ सूक्ष्म उद्यमों के लिए 7.5 प्रतिशत और कमजोर वर्गों के लिए 11.5 प्रतिशत के उप-लक्ष्य को प्राप्त किया (चार्ट V.14)।

V.24. मार्च 2025 के अंत में, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के पास यूसीबी के कुल अग्रिमों में सबसे अधिक हिस्सेदारी थी, हालांकि यह छोटे उद्यमों के कारण घटकर 36.5 प्रतिशत हो गई। इसके विपरीत, सूक्ष्म उद्यमों को ऋण का हिस्सा बढ़ गया, जो छोटे उधारकर्ताओं के लिए बेहतर ऋण प्रवाह का संकेत देता है। 'अन्य' श्रेणी में प्राथमिकता ऋण में गिरावट आई, जिससे वर्ष 2024-25 के दौरान कुल अग्रिमों में कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण की हिस्सेदारी में कमी आई (सारणी V.10)।

सारणी V.10: यूसीबी द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए ऋण की संरचना

(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2024		2025	
	राशि	कुल अग्रिमों में हिस्सेदारी (%)	राशि	कुल अग्रिमों में हिस्सेदारी (%)
1	2	3	4	5
1. कृषि [(i)+(ii)+(iii)]	16,344	4.7	17,032	4.6
(i) फार्म ऋण	12,343	3.6	13,203	3.6
(ii) कृषि अवसंरचना	1,224	0.4	1,028	0.3
(iii) सहायक गतिविधियाँ	2,777	0.8	2,801	0.8
2. सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम [(i) + (ii) + (iii) + (iv)]	1,29,130	37.2	1,35,228	36.5
(i) सूक्ष्म उद्यम	56,340	16.2	62,609	16.9
(ii) लघु उद्यम	48,653	14.0	47,791	12.9
(iii) मध्यम उद्यम	23,554	6.8	24,407	6.6
(iv) खादी और ग्रामोद्योग के लिए अग्रिम ('एमएसएमई के लिए अन्य वित्त' सहित)	583	0.2	422	0.1
3. निर्यात ऋण	723	0.2	101	0.0
4. शिक्षा	3,226	0.9	3,526	1.0
5. आवास	29,269	8.4	30,688	8.3
6. सामाजिक अवसंरचना	1,038	0.3	977	0.3
7. नवीकरणीय ऊर्जा	1,419	0.4	1,546	0.4
8. अन्य	25,288	7.3	17,091	4.6
9. कुल (1 to 8)	**2,06,438**	**59.5**	**2,06,189**	**55.7**
जिनमें से, कमजोर वर्गों को ऋण	42,771	12.3	44,227	11.9

टिप्पणियाँ: 1. वर्ष 2025 के लिए डेटा अनंतिम हैं।
2. प्रतिशत यूसीबी के कुल ऋण के संबंध में हैं।
3. पूर्णांकन के कारण घटकों का योग पूर्ण नहीं हो सकता है।

स्रोत: ऑफ-साइट रिटर्न, आरबीआई।

4. ग्रामीण ऋण सहकारी समितियां

V.25. ग्रामीण ऋण सहकारी समितियां (आरसीसी) जमीनी स्तर पर अपने व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कृषि ऋण वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए सस्ते और समय पर ऋण प्रदान करती हैं, कृषि उत्पादन और ग्रामीण विकास का समर्थन करती हैं। हालांकि, प्रौद्योगिकी, शाखा विस्तार और व्यापार प्रतिनिधियों के माध्यम से वाणिज्यिक बैंकों की बढ़ती पहुंच के कारण, कुल कृषि ऋण में आरसीसी का हिस्सा पिछले कुछ वर्षों में कम हो गया है (सारणी V.11)।

V.26. ग्रामीण ऋण सहकारी संरचना में, मार्च 2025 के अंत में, 2,146 शाखाओं के साथ 34 राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) और 13,825 शाखाओं के माध्यम से 351 जिला सहकारी

[7] 8 जून 2023 के पहले के परिपत्र (जो अब 24 मार्च 2025 के परिपत्र द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है) के तहत यूसीबी को वर्ष 2023-24 में 60 प्रतिशत और 2024-25 में 65 प्रतिशत के अंतरिम लक्ष्य के साथ 2025-26 तक एएनबीसी या सीईओबीएसई के 75 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, का समग्र लक्ष्य प्राप्त करने की आवश्यकता थी।

सारणी V.11: कृषि के लिए ऋण प्रवाह में हिस्सेदारी

(प्रतिशत)

मद	ग्रामीण ऋण सहकारी समितियां	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	वाणिज्यिक बैंक
1	2	3	4
2021-22	13.1	11.0	75.9
2022-23	11.0	11.2	77.8
2023-24	9.5	11.1	79.4
2024-25	9.0	10.8	80.2

टिप्पणि: वाणिज्यिक बैंकों के डेटा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को शामिल नहीं किया गया है।
स्रोत: नाबार्ड (ईएनएसयूआरई पोर्टल)।

केंद्रीय बैंक (डीसीसीबी) संचालित थे। मार्च 2024 के अंत में, अल्पावधिक सहकारी समितियों में, 1,07,641 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) के नेटवर्क ने 6.5 लाख से अधिक गांवों को कवर किया (सारणी V.12)। ये अल्पावधिक संस्थान मुख्य रूप से फसल ऋण प्रदान करते हैं और किसानों और ग्रामीण कारीगरों को कार्यशील पूंजी की सहायता प्रदान करते हैं। मार्च 2024 के अंत में, दीर्घावधिक सहकारी संरचना में 695 शाखाओं के साथ 13 राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी) और 609 प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी) शामिल थे। ये दीर्घावधिक संस्थान कृषि में पूंजी-गहन जरूरतों को पूरा करते हैं, जिसमें भूमि विकास, कृषि मशीनीकरण, लघु सिंचाई, ग्रामीण उद्योग और आवास शामिल हैं।

V.27. आरसीसी अपनी तुलन पत्र संरचना के मामले में यूसीबी से संरचनात्मक रूप से अलग हैं। जबकि यूसीबी मुख्य रूप से धन जुटाने के लिए जमा पर निर्भर करते हैं, आरसीसी उधार पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। मार्च 2024

सारणी V.12 : ग्रामीण ऋण सहकारी समितियों की प्रोफाइल

(मार्च 2024 के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	अल्पावधिक			दीर्घावधिक		ग्रामीण ऋण सहकारी समितियां	
	एसटीसीबी	डीसीसीबी	पीएसीएस	एससीएआरडीबी(पी)	पीसीएआरडीबी (पी)	मार्च-23	मार्च-24
1	2	3	4	5	6	7	8
ए. सहकारी समितियों की संख्या	**34**	**351**	**1,07,641**	**13**	**609**	**1,07,961**	**1,08,648**
बी. तुलन-पत्र संकेतक							
i. स्वामित्व वाली निधि (पूंजी + आरक्षित निधि)	33,392	60,362	59,478	6,743	5,658	1,46,171	1,65,633
ii. जमाराशियां	2,56,819	4,76,610	2,03,532	2,679	1,804	8,77,263	9,41,444
iii. उधार	1,73,116	1,61,728	2,27,931	12,517	16,840	5,32,778	5,92,132
iv. ऋण और अग्रिम	2,94,577	4,13,161	2,12,601	21,048	15,922	8,73,466	9,57,310
v. कुल देयताएं/आस्तियां	4,88,266	7,65,577	4,29,103 ^	28,851	33,324	16,18,761	17,45,121
सी. वित्तीय कार्य-निष्पादन							
i. लाभ में समितियां							
ए. संख्या	32	312	49,238	9	345	48,492	49,936
बी. लाभ की राशि	2,727	3,297	2,609	288	220	8,512	9,142
ii. हानि में समितियां							
ए. संख्या	2	39	37,662	4	263	37,660	37,970
बी. हानि की राशि	35	1,403	3,524	563	421	4,989	5,947
iii. कुल लाभ (+)/हानि (-)	2,691	1,894	-915	-275	-201	3,523	3,195
डी. अनर्जक आस्तियां							
i. राशि	14,537	36,958	53,149 ^ ^	8,070	6,144	1,08,002	1,18,857
ii. बकाया ऋणों के प्रतिशत के रूप में	4.9	8.9	26.2	38.3	38.6	12.4	12.4
ई. मांग और ऋण वसूली अनुपात* (प्रतिशत)	92.4	76.8	77.6	40.8	43.1	-	-

एसटीसीबी: राज्य सहकारी बैंक, डीसीसीबी: जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, पीएसीएस: प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, एससीएआरडीबी: राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, पीसीएआरडीबी: प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक।
पी: डेटा अनंतिम हैं।
^: कार्यशील पूंजी।
^^: कुल अतिदेय।
*: यह अनुपात जून 2023 के अंत में वसूले गए बकाया एनपीए के हिस्से को दर्शाता है।
-: उपलब्ध नहीं।
टिप्पणियाँ: 1. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए डेटा 609 पीसीएआरडीबी में से 608 से संबंधित हैं।
2. पूर्णांकन के कारण घटकों का योग पूर्ण नहीं हो सकता।
स्रोत: नाबार्ड और एनएएफ़एससीओबी।

के अंत में, आरसीसी के लिए 53.9 प्रतिशत की तुलना में जमा राशि यूसीबी की कुल देयताओं का 78.5 प्रतिशत था। इसके विपरीत, आरसीसी के लिए उधार का हिस्सा 33.9 प्रतिशत था, जबकि यूसीबी के मामले में यह 0.8 प्रतिशत था।

V.28. यूसीबी की तुलना में आरसीसी में ऋण, जमा और उधार की तेजी से वृद्धि के कारण, सहकारी समितियों (शहरी और ग्रामीण संयुक्त) की कुल आस्तियों/देयताओं में आरसीसी की हिस्सेदारी मार्च 2024 के अंत में बढ़कर 71.2 प्रतिशत हो गई (चार्ट V.15)।

V.29. ग्रामीण सहकारी समितियों में, अल्पावधिक ऋण सहकारी समितियों की हिस्सेदारी पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ी, जो मार्च 2024 के अंत में 96.4 प्रतिशत तक पहुंच गई (चार्ट V.16ए)। अल्पावधिक और दीर्घावधिक ऋण सहकारी समितियां अपनी तुलन पत्र संरचना और सुदृढ़ता संकेतकों के संदर्भ में भिन्न होती हैं। जबकि अल्पावधिक ऋण सहकारी समितियां मुख्य रूप से जमा पर निर्भर करती हैं, दीर्घावधिक सहकारी समितियां उधार और स्वामित्व वाले धन पर अधिक निर्भर करती हैं। दीर्घावधिक सहकारी समितियों की आस्ति गुणवत्ता अपेक्षाकृत कमजोर बनी हुई है, उनके अल्पावधिक समकक्षों की तुलना में उच्च एनपीए अनुपात है (चार्ट V.16बी)।

चार्ट V.15: सहकारी क्षेत्रों की कुल आस्तियों में ग्रामीण ऋण सहकारी समितियों की हिस्सेदारी

(प्रतिशत)

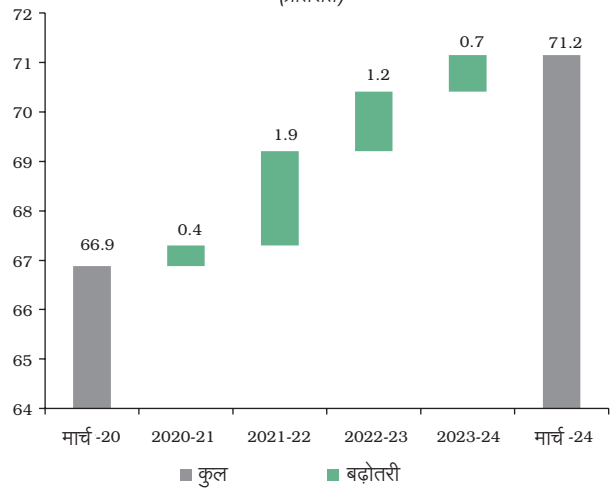

टिप्पणी: पूर्णांकन के कारण घटकों का योग पूर्ण नहीं हो सकता है।
स्रोत: आरबीआई, नाबार्ड और एनएएफएससीओबी।

आरसीसी को यूसीबी की तुलना में ऋण पोर्टफोलियो की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

V.30. आरसीसी लाभदायक रहे, हालांकि वर्ष 2023-24 के दौरान निवल लाभ में कुछ कमी आई, जो पीएसीएस और दीर्घावधिक ऋण सहकारी समितियों में हानि के कारण हुआ। कुल आरसीसी के प्रतिशत के रूप में लाभ में रहने वाले आरसीसी की संख्या मार्च 2024 के अंत में बढ़कर 46.0

चार्ट V.16: अल्पावधिक की तुलना में दीर्घावधिक आरसीसी

ए. आरसीसी की कुल आस्तियों में शेयर

(मार्च अंत में, प्रतिशत)

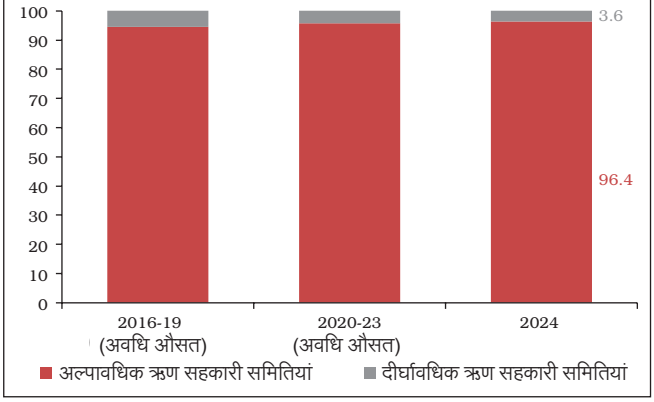

बी. तुलन पत्र और सुदृढ़ता संकेतक

(मार्च अंत 2024, प्रतिशत)

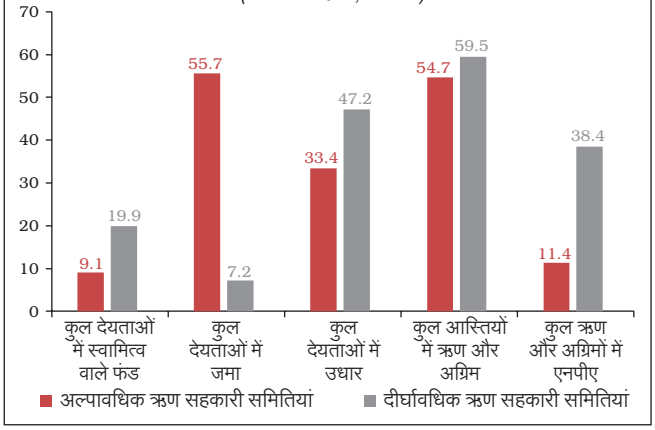

स्रोत: नाबार्ड और एनएएफ़एससीओबी।

प्रतिशत हो गई, जो एक वर्ष पहले 44.9 प्रतिशत थी। वर्ष के दौरान आरसीसी की आस्ति गुणवत्ता स्थिर रही, क्योंकि एसटीसीबी, डीसीसीबी, पीसीएआरडीबी में सुधार पीएसीएस और एससीएआरडीबी में गिरावट से संतुलित हो गया।

V.31. अप्रैल 2025 में, रिज़र्व बैंक ने ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए एक साझा सेवा इकाई (एसएसई) की स्थापना के लिए विनियामक अनुमोदन प्रदान किया। भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के सहयोग से नाबार्ड, सहकार सारथी प्राइवेट लिमिटेड (एसएसपीएल) नामक एक एसएसई की स्थापना कर रहा है, जो ग्रामीण सहकारी बैंकों को केंद्रीकृत तकनीकी, परिचालन और सहायता सेवाएं प्रदान करेगा। इस पहल का उद्देश्य सेवा की गुणवत्ता बढ़ाना, लागत कम करना और उभरती प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाना है। इसके अलावा, सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए, 1 नवंबर 2025 से एसटीसीबी और डीसीसीबी को शामिल करने के लिए रिज़र्व बैंक-एकीकृत ओम्बड्समैन योजना का विस्तार किया गया है।

4.1. अल्पावधिक ग्रामीण ऋण सहकारी समितियां

V.32. अल्पावधिक ग्रामीण ऋण सहकारी समितियां - जिनमें शीर्ष स्तर पर एसटीसीबी, जिला स्तर पर डीसीसीबी और आधार स्तर पर पीएसीएस शामिल हैं - कृषि क्षेत्र की अल्पावधिक और मौसमी ऋण जरूरतों और डेयरी और मत्स्य पालन जैसी संबद्ध गतिविधियों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। समय के साथ, गैर-कृषि गतिविधि और सूक्ष्म वित्त को शामिल करने के लिए उनके परिचालन का विस्तार हो रहा है। अल्पावधिक सहकारी संरचना दो, तीन या मिश्रित-स्तरीय प्रारूपों में संचालित होती है। दो-स्तरीय प्रणालियां बड़े पैमाने पर उत्तर-पूर्वी राज्यों में प्रचलित हैं, जहां एसटीसीबी अपनी शाखाओं और पीएसीएस के माध्यम से सीधे ऋण देते हैं, जबकि त्रि-स्तरीय प्रणाली में, एसटीसीबी जिला स्तर पर काम करने वाले डीसीसीबी के लिए शीर्ष बैंकों के रूप में कार्य करते हैं। मिश्रित स्तरीय संरचना वाले राज्यों में, एसटीसीबी कुछ जिलों में सीधे और अन्य में डीसीसीबी के माध्यम से कार्य करते हैं।

4.1.1. राज्य सहकारी बैंक

V.33. अल्पावधिक सहकारी ऋण संरचना के शीर्ष स्तर पर स्थित एसटीसीबी डीसीसीबी और पीएसीएस के लिए संसाधनों को एकत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सहकारी ऋण प्रणाली के निम्न स्तरों को पुनर्वित्त, चलनिधि सहायता और तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं, जिससे अल्पावधिक कृषि ऋण के प्रवाह की सुविधा मिलती है।

तुलन-पत्र परिचालन

V.34. वर्ष 2024-25 के दौरान, एसटीसीबी के तुलन-पत्र में एक वर्ष पहले के 8.1 प्रतिशत की तुलना में 7.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। देयताओं के पक्ष पर, जमा वृद्धि पिछले वर्ष के 6.0 प्रतिशत से बढ़कर 6.8 प्रतिशत हो गई (सारणी V.13)।

सारणी V.13: राज्य सहकारी बैंकों की देयताएँ और आस्तियां

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत भिन्नता	
	2024	2025[पी]	2023-24	2024-25[पी]
1	2	3	4	5
1. पूंजी	10,531 (2.2)	10,992 (2.1)	7.7	4.4
2. आरक्षित निधि	22,861 (4.7)	26,220 (5.0)	11.3	14.7
3. जमा	2,56,819 (52.6)	2,74,183 (52.2)	6.0	6.8
4. उधार	1,73,116 (35.5)	1,89,549 (36.1)	11.7	9.5
5. अन्य देयताएँ	24,940	24,781 (4.7)	2.9	-0.6
कुल देयताएँ/आस्तियां	**4,88,266 (100.0)**	**5,25,725 (100.0)**	**8.1**	**7.7**
1. नकद और बैंक शेष	22,661 (4.6)	22,764 (4.3)	6.7	0.5
2. निवेश	1,55,826 (31.9)	1,68,690 (32.1)	4.8	8.3
3. ऋण और अग्रिम	2,94,577 (60.3)	3,20,004 (60.9)	10.9	8.6
4. संचित हानि	1,146 (0.2)	1,185 (0.2)	-15.0	3.4
5. अन्य आस्तियां	14,057	13,081 (2.5)	-6.3	-6.9

पी: अनंतिम।

टिप्पणियाँ: 1. कोष्ठक में आंकड़े कुल देयताओं/आस्तियों (प्रतिशत में) का अनुपात हैं।
2. पूर्णांकन के कारण घटकों का योग पूर्ण नहीं हो सकता है।

स्रोत: नाबार्ड।

कुल जमाओं में चालू खाता और बचत खाता (कासा) जमा की हिस्सेदारी घटकर 17.4 प्रतिशत रह गई (एक वर्ष पहले 18.6 प्रतिशत), जो उनके सीमित शाखा नेटवर्क को दर्शाती है। इसके विपरीत, नाबार्ड से उधार लेने के कारण उधार का हिस्सा एक वर्ष पहले के 35.5 प्रतिशत से बढ़कर 36.1 प्रतिशत हो गया।

V.35. आस्तियों के पक्ष पर, ऋण और अग्रिम में 8.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो एक वर्ष पहले इसी महीने में 10.9 प्रतिशत थी। कृषि ऋण कुल ऋण और अग्रिमों का 43.4 प्रतिशत था, जिसमें से 77.7 प्रतिशत फसल ऋण/अल्पावधिक ऋण थे। ऋण वृद्धि जमा वृद्धि को पार करने के साथ, एसटीसीबी का ऋण-जमा अनुपात मार्च 2025 के अंत में बढ़कर 116.7 प्रतिशत हो गया, जो एक वर्ष पहले 114.7 प्रतिशत था। अन्य बैंकों के साथ मियादी जमा के रूप में रखे गए निवेश में उच्च वृद्धि के कारण, कुल निवेश में एसएलआर निवेश की हिस्सेदारी मार्च 2025 के अंत में घटकर 45.8 प्रतिशत हो गई, जो एक वर्ष पहले 51.2 प्रतिशत थी।

V.36. मार्च 2025 के अंत में, 34 एसटीसीबी में से 24 अनुसूचित बैंक थे। जमा और ऋण दोनों के संदर्भ में अनुसूचित एसटीसीबी की व्यावसायिक वृद्धि वर्ष 2024-25 के दौरान कम हो गई (सारणी V.14)।

सारणी V.14: अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों के चुनिंदा तुलन पत्र संकेतक
(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2024	2025
1	2	3
जमाराशियां	2,15,540	2,19,976
	(5.4)	(2.1)
ऋण	2,78,147	2,97,426
	(8.8)	(6.9)
एसएलआर निवेश	77,525	79,410
	(3.8)	(2.4)
क्रेडिट के साथ एसएलआर निवेश	3,55,671	3,76,836
	(7.6)	(6.0)

टिप्पणियाँ: 1. डेटा संबंधित वर्ष के मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित है।
2. कोष्ठक में आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत में वृद्धि दर है।

स्रोत: आरबीआई अधिनियम की धारा 42 के तहत फॉर्म बी।

लाभप्रदता

V.37. वर्ष 2024-25 के दौरान, प्रावधान में गिरावट के बावजूद, एसटीसीबी के निवल लाभ में गिरावट आई क्योंकि परिचालन व्यय में तेजी से वृद्धि हुई, और ब्याज व्यय में वृद्धि ब्याज आय में वृद्धि से अधिक हो गई (सारणी V.15)। व्यय किए गए ब्याज में वृद्धि आंशिक रूप से कम लागत वाली सीएएसए जमा राशि के हिस्से में गिरावट को दर्शाती है।

V.38. वर्ष 2024-25 के दौरान, 34 एसटीसीबी में से 32 ने लाभ की सूचना दी। उत्तरी, उत्तर-पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में एसटीसीबी ने वर्ष के दौरान लाभप्रदता में सुधार की सूचना दी, जबकि पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र में एसटीसीबी के लाभ में कमी आई (चार्ट V.17 और परिशिष्ट सारणी V.3)।

सारणी V.15: राज्य सहकारी बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

मद	राशि (₹ करोड़ में)		भिन्नता (प्रतिशत में)	
	2023-24	2024-25[P]	2023-24	2024-25[P]
1	2	3	4	5
ए. आय (i +ii)	**32,401**	**36,134**	**17.2**	**11.5**
	(100.0)	**(100.0)**		
i. ब्याज आय	30,974	34,329	16.2	10.8
	(95.6)	(95.0)		
ii. अन्य आय	1,427	1,804	43.6	26.4
	(4.4)	(5.0)		
बी. व्यय (i+ii+iii)	**29,710**	**33,524**	**17.9**	**12.8**
	(100.0)	**(100.0)**		
i. व्यय किए हुए ब्याज	23,793	27,158	24.9	14.1
	(80.1)	(81.0)		
ii. प्रावधान और आकस्मिकताएं	1,979	1,810	3.0	-8.6
	(6.7)	(5.4)		
iii. परिचालन व्यय	3,938	4,557	-6.8	15.7
	(13.3)	(13.6)		
जिसमें से, मजदूरी विधेयक	2,077	2,178	0.8	4.9
	(7.0)	(6.5)		
सी. लाभ				
i. निवल ब्याज आय	7,181	7,171	-5.7	-0.1
ii. परिचालन लाभ	4,670	4,419	6.7	-5.4
iii. निवल लाभ	2,691	2,609	9.5	-3.0

पी: अनंतिम।

टिप्पणियाँ: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल आय/व्यय (प्रतिशत में) के अनुपात में हैं।
2. पूर्णांकन के कारण घटकों का योग पूर्ण नहीं हो सकता है।

स्रोत: नाबार्ड।

चार्ट V.17: राज्य सहकारी बैंक के लाभ का क्षेत्रवार वितरण

(राशि ₹ करोड़ में)

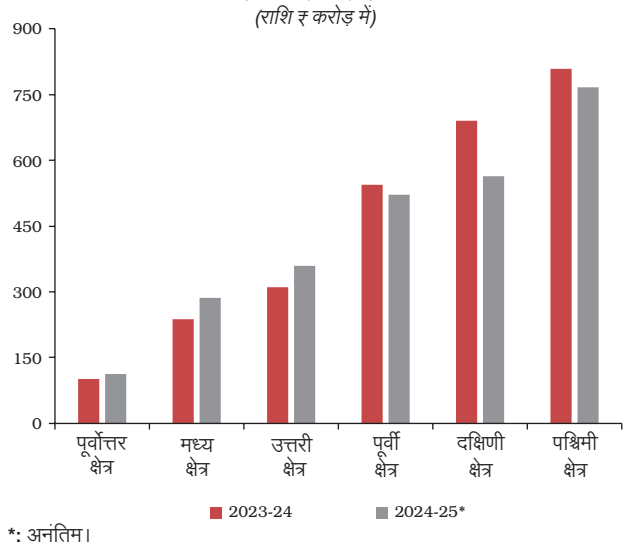

*: अनंतिम।
स्रोत: नाबार्ड।

आस्ति गुणवत्ता

V.39. एसटीसीबी की आस्ति गुणवत्ता में लगातार चौथे वर्ष सुधार हुआ, जीएनपीए अनुपात मार्च 2021 के अंत में 6.7 प्रतिशत से घटकर मार्च 2025 के अंत में 4.8 प्रतिशत हो गया। कुल एनपीए में संदिग्ध आस्तियों का हिस्सा एक वर्ष पहले के 56.7 प्रतिशत से घटकर 50.5 प्रतिशत हो गया (सारणी V.16)। वर्ष के दौरान जीएनपीए में कमी और प्रावधान कवरेज अनुपात को दर्शाते हुए, निवल एनपीए अनुपात 2.0 प्रतिशत पर स्थिर रहा। मध्य क्षेत्र को छोड़कर, अन्य सभी क्षेत्रों में जीएनपीए अनुपात में गिरावट आई (परिशिष्ट सारणी V.3)।

पूंजी पर्याप्तता

V.40. समेकित स्तर पर, एसटीसीबी अच्छी तरह से पूंजीकृत रहे, सीआरएआर मार्च 2025 के अंत में बढ़कर 13.6 प्रतिशत हो गया, जो एक वर्ष पहले 12.9 प्रतिशत था (चार्ट V.18)। बैंक स्तर पर, केवल दो एसटीसीबी ने विनियामक न्यूनतम 9 प्रतिशत से कम सीआरएआर की सूचना दी।

4.1.2. जिला सहकारी केंद्रीय बैंक

V.41. डीसीसीबी त्रि-स्तरीय सहकारी बैंकिंग संरचना में दूसरे स्तर के रूप में कार्य करते हैं। वे सार्वजनिक जमा, एसटीसीबी से उधार और नाबार्ड से पुनर्वित्त के माध्यम से धन जुटाते हैं। डीसीसीबी के पास अपने बड़े शाखा नेटवर्क के कारण एसटीसीबी की तुलना में सीएएसए जमा तक बेहतर पहुंच है।

सारणी V.16: राज्य सहकारी बैंकों के सुदृढ़ता संकेतक

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	मार्च के अंत में		घट-बढ़ प्रतिशत	
	2024	2025[पी]	2023-24	2024-25[पी]
1	2	3	4	5
ए. कुल एनपीए (i+ii+iii)	14,537	15,407	1.7	6.0
i. अवमानक	4,974 (34.2)	5,980 (38.8)	7.9	20.2
ii. संदिग्ध	8,237 (56.7)	7,782 (50.5)	-0.7	-5.5
iii. हानि	1,326 (9.1)	1,645 (10.7)	-4.9	24.1
बी. सकल एनपीए अनुपात (%)	4.9	4.8		
सी. निवल एनपीए अनुपात (%)	2.0	2.0		
डी. प्रावधान कवरेज अनुपात (%)	68.5	64.1		
ई. मांग और वसूली अनुपात (%)	92.4	87.5		

पी: अनंतिम।
टिप्पणियाँ: 1. कोष्ठक में आंकड़े कुल एनपीए (प्रतिशत में) में शेयर हैं।
2. वसूली और मांग अनुपात जून 2024 और 2025 के अंत तक बकाया मांग राशि (देय राशि) के उस हिस्से को दर्शाता है जिसकी वसूली हो चुकी है।
स्रोत: नाबार्ड।

चार्ट V.18: राज्य सहकारी बैंकों की पूंजी पर्याप्तता

(मार्च के अंत में, प्रतिशत)

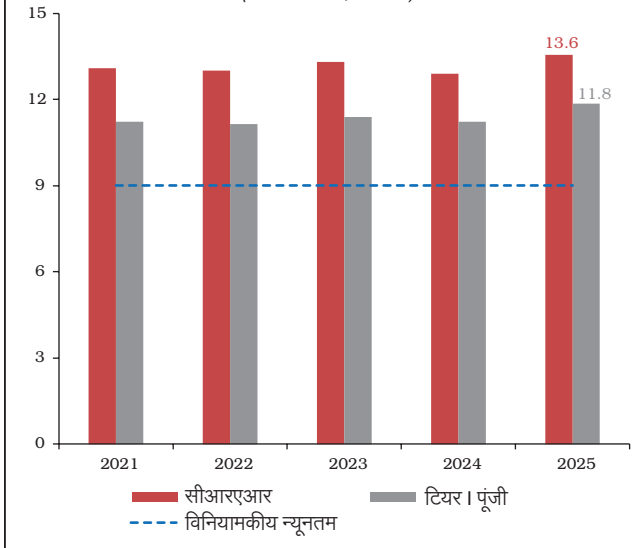

स्रोत: नाबार्ड।

उनकी कुल प्रगति और कृषि प्रगति पीएसीएस/समितियों की ओर झुकी हुई है।

तुलन-पत्र परिचालन

V.42. वर्ष 2024-25 के दौरान, डीसीसीबी के तुलन-पत्र की वृद्धि मुख्य रूप से देयताओं के पक्ष में जमा वृद्धि और आस्तियों के पक्ष पर ऋण और अग्रिम में मंदी को दर्शाती है (सारणी V.17)। देयताओं के मामले में सीएएसए जमा की हिस्सेदारी कुल जमा का 40.5 प्रतिशत है। एसटीसीबी और नाबार्ड से ली गई उधारी डीसीसीबी की कुल उधारी का क्रमशः 89.3 प्रतिशत और 9.2 प्रतिशत है।

V.43. आस्तियों के मामले में, ऋण में वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में कम रही, जबकि निवेश में वृद्धि हुई। बहरहाल, ऋण वृद्धि जमा वृद्धि से अधिक होने के साथ, ऋण-जमा अनुपात मार्च 2025 के अंत में बढ़कर 87.6 प्रतिशत हो गया, जो एक वर्ष पहले 86.7 प्रतिशत था। कुल ऋण और अग्रिमों में कृषि ऋण का हिस्सा पिछले वर्ष के 54.6 प्रतिशत थोड़ा सा घटकर 53.6 प्रतिशत हो गया। डीसीसीबी के निवेश को मुख्य रूप से अन्य बैंकों (57.0 प्रतिशत) के साथ मीयादी जमा के रूप में रखा गया, जबकि सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) निवेश कुल निवेश का 38.4 प्रतिशत रहा।

लाभप्रदता

V.44. वर्ष 2024-25 के दौरान, डीसीसीबी की निवल ब्याज आय में वृद्धि कम हो गई क्योंकि ब्याज आय की तुलना में ब्याज व्यय तेजी से बढ़ी। हालांकि, निवल लाभ में 12.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो बेहतर आस्ति गुणवत्ता और अन्य आय में वृद्धि के कारण कम प्रावधान आवश्यकताओं की वजह से है (सारणी V.18)।

सारणी V.17: जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत भिन्नता	
	2024	2025#	2023-24	2024-25#
1	2	3	4	5
1. पूंजी	28,661 (3.7)	30,940 (3.7)	8.2	8.0
2. आरक्षित निधियां	31,701 (4.1)	36,472 (4.4)	10.3	15.1
3. जमाराशियाँ	4,76,610 (62.3)	5,09,002 (61.5)	10.0	6.8
4. उधार	1,61,728 (21.1)	1,79,760 (21.7)	9.9	11.1
5. अन्य देयताएं	66,876 (8.7)	71,450 (8.6)	8.7	6.8
कुल देयताएं/आस्तियां	**7,65,577 (100.0)**	**8,27,625 (100.0)**	**9.8**	**8.1**
1. नकदी और बैंक शेष	38,705 (5.1)	40,904 (4.9)	14.6	5.7
2. निवेश	2,65,692 (34.7)	2,88,716 (34.9)	7.2	8.7
3. ऋण और अग्रिम	4,13,161 (54.0)	4,45,748 (53.9)	11.4	7.9
4. संचित हानि	9,405 (1.2)	10,576 (1.3)	12.5	12.5
5. अन्य आस्तियां	38,615 (5.0)	41,681 (5.0)	6.1	7.9

पी: अनंतिम।

टिप्पणियाँ: 1. कोष्ठक में आंकड़े कुल देयताएं/आस्तियों (प्रतिशत में) के अनुपात में हैं।
2. पूर्णांकन के कारण घटकों का योग पूर्ण नहीं हो सकता है।

स्रोत: नाबार्ड।

सारणी V.18: जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

मद	राशि (₹ करोड़ में)		प्रतिशत भिन्नता	
	2023-24	2024-25#	2023-24	2024-25#
1	2	3	4	5
ए. आय (i +ii)	**52,408 (100.0)**	**58,181 (100.0)**	**13.2**	**11.0**
i. ब्याज आय	49,989 (95.4)	55,520 (95.4)	13.7	11.1
ii. अन्य आय	2,420 (4.6)	2,661 (4.6)	3.3	10.0
बी. व्यय (i +ii+iii)	**50,515 (100.0)**	**56,057 (100.0)**	**13.7**	**11.0**
i. व्यय किया गया ब्याज	32,731 (64.8)	37,543 (67.0)	18.6	14.7
ii. प्रावधान और आकस्मिकताएं	5,733 (11.3)	5,700 (10.2)	1.7	-0.6
iii. परिचालनगत व्यय	12,051 (23.9)	12,815 (22.9)	7.7	6.3
जिसमें से, मजदूरी विधेयक	7,430 (14.7)	7,778 (13.9)	7.0	4.7
सी. लाभ				
i. निवल ब्याज आय	17,257	17,977	5.4	4.2
ii. परिचालन लाभ	7,627	7,823	1.4	2.6
iii. निवल लाभ	1,894	2,124	0.7	12.1

पी: अनंतिम।

टिप्पणियाँ: 1. कोष्ठक में आंकड़े कुल देयताएं/आस्तियों (प्रतिशत में) के अनुपात में हैं।
2. पूर्णांकन के कारण घटकों का योग पूर्ण नहीं हो सकता है।

स्रोत: नाबार्ड।

V.45. 2024-25 के दौरान, 301 लाभ कमाने वाले डीसीसीबी और 50 घाटे में चल रहे डीसीसीबी थे। लाभ कमाने वाले डीसीसीबी भौगोलिक रूप से सभी क्षेत्रों में अच्छी तरह से वितरित थे, जिनका सकेंद्रण उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक में अपेक्षाकृत अधिक था। वर्ष के दौरान घाटे में चल रहे डीसीसीबी की संख्या में वृद्धि हुई। घाटे में चल रहे 50 डीसीसीबी में से लगभग 82 प्रतिशत पांच राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार और महाराष्ट्र में केंद्रित थे (परिशिष्ट सारणी V.4)।

आस्ति गुणवत्ता

V.46. डीसीसीबी की आस्ति गुणवत्ता में लगातार पांचवें वर्ष सुधार हुआ, मार्च 2025 के अंत में जीएनपीए अनुपात घटकर 8.7 प्रतिशत हो गया। हालांकि, जीएनपीए अनुपात एसटीसीबी की तुलना में अधिक रहा (चार्ट V.19)। आस्ति गुणवत्ता में सुधार व्यापक आधार पर किया गया और पश्चिमी क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्रों में जीएनपीए अनुपात में गिरावट आई (परिशिष्ट सारणी V.4)। मध्य क्षेत्र में डीसीसीबी में सबसे अधिक जीएनपीए अनुपात है, इसके बाद पश्चिमी क्षेत्र में हैं। बढ़े हुए प्रावधान कवरेज अनुपात के साथ जीएनपीए अनुपात में गिरावट के परिणामस्वरूप मार्च 2025 के अंत में निवल एनपीए अनुपात एक वर्ष पहले 3.4 प्रतिशत से घटकर 3.0 प्रतिशत हो गया (सारणी V.19)।

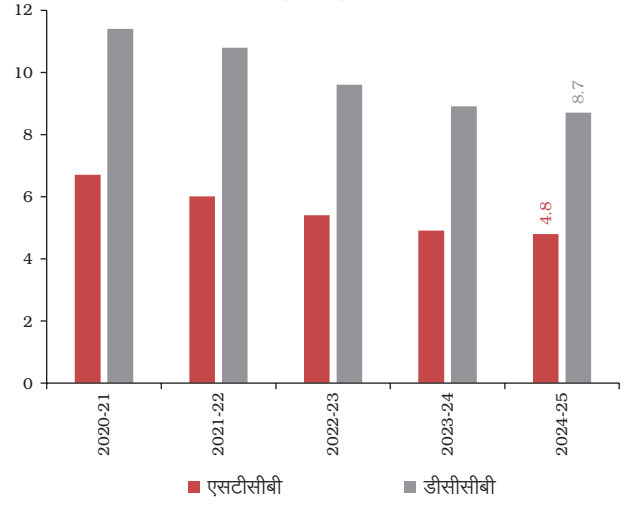

चार्ट V.19 : एनपीए अनुपात : एसटीसीबी की तुलना में डीसीसीबी

(प्रतिशत)

एसटीसीबी: राज्य सहकारी बैंक; डीसीसीबी : जिला सहकारी केंद्रीय बैंक।

स्रोत: नाबार्ड।

सारणी V.19: जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के सुदृढ़ता संकेतक

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत भिन्नता	
	2024	2025पी	2023-24	2024-25पी
1	2	3	4	5
ए. कुल एनपीए (i+ ii + iii)	36,958	38,709	3.5	4.7
i) अवमानक	13,433 (36.3)	14,288 (36.9)	7.1	6.4
ii) संदिग्ध	20,912 (56.6)	21,397 (55.3)	0.8	2.3
iii) हानि	2,612 (7.1)	3,024 (7.8)	7.0	15.8
बी. सकल एनपीए अनुपात (प्रतिशत)	8.9	8.7		
सी. निवल एनपीएअनुपात (प्रतिशत)	3.4	3.0		
डी. प्रावधान कवरेज अनुपात (प्रतिशत)	83.9	84.3		
ई. मांग और वसूली अनुपात (प्रतिशत)	76.8	76.4		

पी: अनंतिम।

टिप्पणियाँ: 1. कोष्ठक में आंकड़े कुल एनपीए (प्रतिशत में) के अनुपात में हैं।
2. वसूली और मांग अनुपात बकाया मांग राशि (देय राशि) के हिस्से का पता करता है जिसे जून 2024 और 2025 के अंत में वसूल किया गया है।

स्रोत: नाबार्ड।

पूंजी पर्याप्तता

V.47. पिछले कुछ वर्षों में, डीसीसीबी का समेकित सीआरएआर मोटे तौर पर लगभग 12 प्रतिशत पर स्थिर रहा (चार्ट V.20)। वर्ष 2024-25 के दौरान, 9.0 प्रतिशत की विनियामक आवश्यकता से कम सीआरएआर वाले डीसीसीबी की संख्या एक वर्ष पहले के 39 से घटकर 38 हो गई। इनमें से 75 प्रतिशत से अधिक डीसीसीबी चार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, मध्य प्रदेश (14), पंजाब (6), राजस्थान (5) और महाराष्ट्र (4) में केंद्रित थे।

4.1.3. प्राथमिक कृषि ऋण समितियां

V.48. पीएसीएस अल्पावधिक ऋण सहकारी समितियों की जमीनी स्तर की शाखा है।[8] पीएसीएस का स्वामित्व सदस्य

[8] पीएसीएस बैंकिंग विनियमन अधिनियम के दायरे से बाहर हैं और उन्हें अपने नाम के हिस्से के रूप में या अपने व्यवसाय के संबंध में, "बैंक", "बैंकर" या "बैंकिंग" शब्दों का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।

चार्ट V.20: जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों की पूंजी पर्याप्तता

(मार्च के अंत में, प्रतिशत)

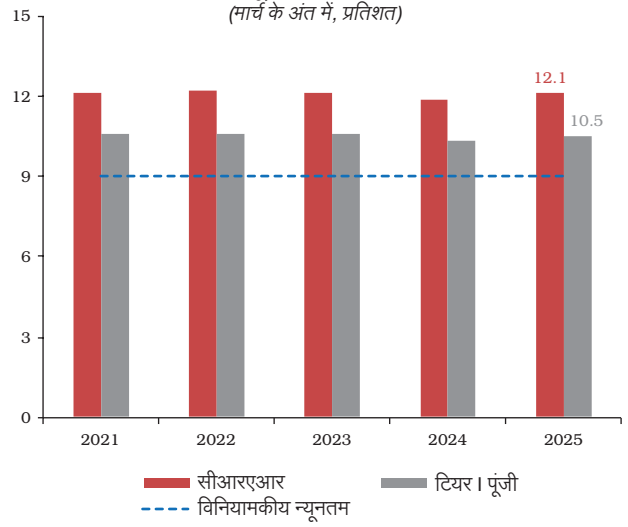

स्रोत : नाबार्ड।

व्यक्तियों, ज्यादातर किसानों के पास है, और इसका उद्देश्य सदस्यों के बीच मितव्ययिता और आपसी मदद को बढ़ावा देना है। वे सदस्यों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और कृषि उपज की इनपुट आपूर्ति, भंडारण और विपणन जैसी ऋण-आधारित सेवाएं प्रदान करते हैं। मार्च 2024 के अंत में, पीएसीएस के 16.37 करोड़ सदस्य थे, और उन्होंने 4.95 करोड़ उधारकर्ताओं को सेवा प्रदान की। कुल सदस्यों में से 44.2 प्रतिशत छोटे किसान और 24.9 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से थे। उधारकर्ता और सदस्य अनुपात – पीएसीएस की ऋण पैठ को मापने के लिए एक मीट्रिक - मार्च 2024 के अंत में 30.2 प्रतिशत था, जबकि एक वर्ष पहले यह 30.7 प्रतिशत था (परिशिष्ट सारणी V.5)।

V.49. वर्ष 2023-24 के दौरान, पीएसीएस के कुल संसाधनों में वृद्धि एक वर्ष पहले के 14.2 प्रतिशत से घटकर 9.8 प्रतिशत हो गई। इसके कारण जमा वृद्धि में तेज मंदी आई, जो उनके कुल संसाधनों का 41.5 प्रतिशत थी। कुल बकाया ऋणों और अग्रिमों का 80 प्रतिशत से अधिक छोटी अवधि के लिए था और कृषि के लिए बढ़ाया गया था। अल्पावधिक ऋणों की वृद्धि में तेज कमी ने कुल ऋणों और अग्रिमों की वृद्धि में गिरावट में योगदान दिया (परिशिष्ट सारणी V.6)।

V.50. पश्चिमी क्षेत्र – पीएसीएस की कुल संख्या में 29.4 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ – इस क्षेत्र पर हावी है। हालांकि, दक्षिणी क्षेत्र जमा, ऋण और अग्रिम के मामले में क्रमशः 76.9 प्रतिशत और 49.6 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ हावी रहा। वर्ष 2023-24 के दौरान, लाभ की रिपोर्ट करने वाले पीएसीएस की संख्या एक वर्ष पहले के 47,794 से बढ़कर 49,238 हो गई। घाटे में चल रहे पीएसीएस की संख्या भी पिछले वर्ष के 37,357 से थोड़ी बढ़कर 37,662 हो गई। कुल मिलाकर, पीएसीएस ने पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2023-24 में कम निवल हानि दर्ज की। क्षेत्रीय स्तर पर, उत्तरी, उत्तर-पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में पीएसीएस ने निवल लाभ की सूचना दी, जबकि दक्षिणी क्षेत्र और मध्य क्षेत्र ने निवल हानि की सूचना दी (परिशिष्ट सारणी V.7)। हालांकि, पीएसीएस की आस्ति गुणवत्ता में गिरावट आई, जीएनपीए अनुपात मार्च 2023 के अंत में 23.3 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2024 के अंत में 26.2 प्रतिशत हो गया।

V.51. बीते वर्षों में, पीएसीएस को आधुनिक, बहु-कार्यात्मक संस्थाओं में बदलने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। भारत सरकार वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक पीएसीएस के कम्प्यूटरीकरण के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना का संचालन कर रही है, ताकि तकरीबन 80,000 से अधिक पीएसीएस को एक एकीकृत उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) प्लेटफॉर्म पर शामिल किया जा सके ताकि डीसीसीबी और एसटीसीबी के साथ लेखांकन, पर्यवेक्षण और लिंकेज को मजबूत किया जा सके। भारत सरकार ने पाँच वर्ष के भीतर 2 लाख नई बहुउद्देशीय पीएसीएस, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियां स्थापित करने की योजना भी शुरू की। ग्रामीण सेवाओं और वित्तीय उत्पादों की एक विस्तृत शृंखला प्रदान करने के लिए पीएसीएस को 'कोऑपरेटिव स्टैक' डिजिटल इकोसिस्टम में भी एकीकृत किया जा रहा है। इसके अलावा, अभिसरण पहल ने पीएसीएस को सामान्य सेवा केंद्रों, जन औषधि केंद्रों और एलपीजी और उर्वरक वितरण बिंदुओं के रूप में कार्य करने में

सक्षम बनाया, जिससे अंतिम-क्षोर वितरण में उनकी भूमिका का विस्तार हुआ। इन उपायों का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को गहरा करना, परिचालन व्यवहार्यता में सुधार करना और सहकारी ऋण संरचना में पीएसीएस को व्यापक ग्रामीण सेवा संस्थानों के रूप में फिर से स्थापित करना है।

4.2. दीर्घावधिक ग्रामीण ऋण सहकारी समितियां

V.52. मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दीर्घावधिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दीर्घावधिक ग्रामीण ऋण सहकारी समितियों की स्थापना की गई थी। दीर्घावधिक संरचना में राज्य स्तर पर एससीएआरडीबी और कुछ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में जिला/तालुका स्तर पर पीसीएआरडीबी शामिल हैं।[9]

V.53. मार्च 2024 के अंत में, 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में दीर्घावधिक ग्रामीण ऋण सहकारी समितियां काम कर रही थीं, जो एकात्मक, संघीय या मिश्रित-स्तरीय संरचनाओं के तहत काम कर रही थीं।[10] एकात्मक संरचना में, एससीएआरडीबी राज्य भर में शाखाओं के अपने नेटवर्क के माध्यम से कार्य करता है, जिसमें ग्राहक सदस्यता के माध्यम से सीधे बैंक से जुड़े होते हैं और इसकी शाखाओं से ऋण प्राप्त करते हैं। संघीय ढांचे के तहत, एससीएआरडीबी जिला या तालुका स्तर पर संचालित सभी संबद्ध पीसीएआरडीबी के लिए शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करता है, जो बदले में, सदस्यों को नामांकित करता है और उन्हें ऋण प्रदान करता है। कुछ राज्यों में, दीर्घावधिक ग्रामीण ऋण सहकारी समितियां एक मिश्रित संरचना का पालन करती हैं, जिसमें एससीएआरडीबी पीसीएआरडीबी और अपने स्वयं के शाखा नेटवर्क दोनों के माध्यम से काम करते हैं।

V.54. एससीएआरडीबी और पीसीएआरडीबी का व्यवसाय मॉडल उधार पर निर्भर करता है, जहां एससीएआरडीबी मुख्य रूप से नाबार्ड से उधार लेते हैं, जबकि पीसीएआरडीबी एससीएआरडीबी से वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं (चार्ट V.21ए)। ऋण और अग्रिमों ने पीसीएआरडीबी के सापेक्ष एससीएआरडीबी में आस्तियों का एक बड़ा हिस्सा बनाया (चार्ट V.21बी)।

4.2.1. राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

V.55. मार्च 2024 के अंत में, एससीएआरडीबी 695 शाखाओं के साथ 13 राज्यों में परिचालित थे। जिनमें से 46.5

चार्ट V.21: दीर्घावधिक ग्रामीण सहकारी समितियों की देयताएं और आस्तियों का संघटन

(मार्च 2024 के अंत में)

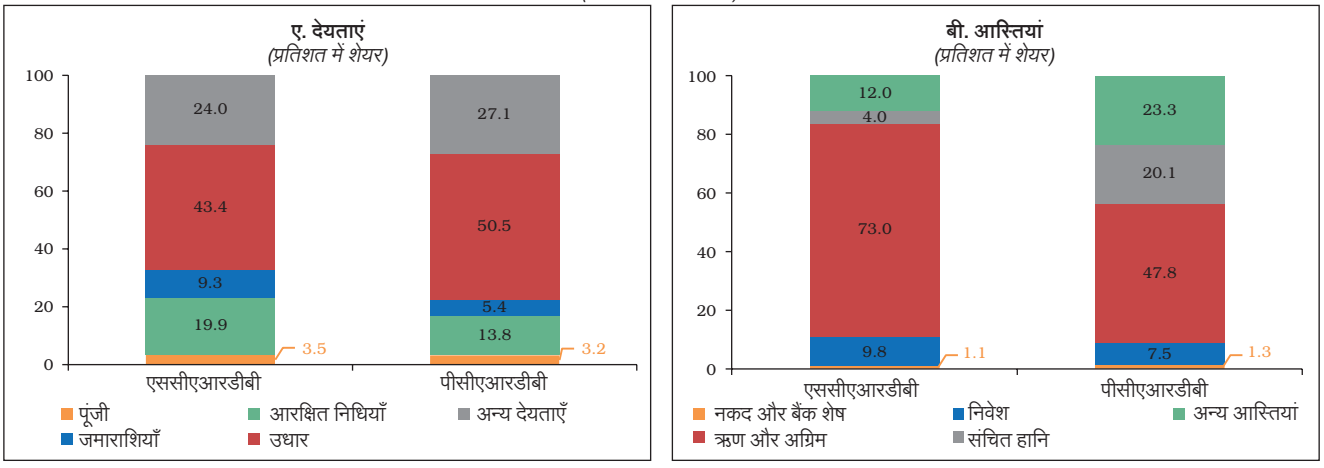

एससीएआरडीबी : राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक; पीसीएआरडीबी: प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक।
स्रोत : नाबार्ड।

[9] कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (राज्य और प्राथमिक दोनों) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अधीन नहीं हैं, और उन्हें गैर-सदस्यों से मांग जमाराशियाँ जुटाने की अनुमति नहीं है।

[10] दीर्घावधिक ग्रामीण ऋण सहकारी समितियां गुजरात, जम्मू और कश्मीर, पुडुचेरी, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में एकात्मक; हरियाणा, कर्नाटक, केरल, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु में संघीय संरचना; और हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में मिश्रित संरचना में काम करती हैं।

प्रतिशत शाखाएँ उत्तर प्रदेश में थीं। वर्ष 2023-24 के दौरान एससीएआरडीबी (संचित घाटे का निवल) के समेकित तुलन पत्र के आकार में मामूली सुधार हुआ, जिसके कारण ऋण और अग्रिमों के और अन्य आस्तियों में वृद्धि हुई (परिशिष्ट सारणी V.8)। वर्ष के दौरान एससीएआरडीबी के संचित घाटे में वृद्धि हुई, जो उत्तरी क्षेत्र में एससीएआरडीबी द्वारा किए गए घाटे में तेज वृद्धि से प्रेरित है।

V.56. समेकित स्तर पर, वर्ष 2023-24 के दौरान एससीएआरडीबी का वित्तीय प्रदर्शन कमजोर हो गया, पिछले वर्ष में 38.9 प्रतिशत की वृद्धि के बाद कुल आय में 27.9 प्रतिशत की गिरावट आई (परिशिष्ट सारणी V.9)। यह गिरावट मुख्य रूप से गैर-ब्याज आय में तेज गिरावट के कारण हुई। व्यय पक्ष पर, कुल व्यय में 8.9 प्रतिशत की गिरावट आई, जो परिचालन व्यय में कमी से प्रेरित है, हालांकि ब्याज व्यय और प्रावधान में वृद्धि हुई। कुल मिलाकर, परिचालन लाभ में 54.4 प्रतिशत की गिरावट आई, और निवल लाभ ऋणात्मक हो गया (परिशिष्ट सारणी V.9)।

V.57. वर्ष 2023-24 के दौरान एससीएआरडीबी की आस्ति गुणवत्ता में कमी आई, जीएनपीए अनुपात मार्च 2024 के अंत में बढ़कर 38.3 प्रतिशत हो गया, जो एक वर्ष पहले 36.5 प्रतिशत था। एनपीए की संरचना के संदर्भ में, संदिग्ध आस्तियों की हिस्सेदारी हावी रही, जो मार्च 2024 के अंत में कुल एनपीए का 67.4 प्रतिशत थी। मांग और वसूली अनुपात एक वर्ष पहले के 44.8 प्रतिशत से घटकर 40.8 प्रतिशत हो गया, जो वसूली में कमी का संकेत देता है (परिशिष्ट सारणी V.10)।

V.58. क्षेत्रीय स्तर पर, एससीएआरडीबी के वित्तीय प्रदर्शन ने वर्ष 2023-24 के दौरान व्यापक भिन्नता प्रदर्शित की (परिशिष्ट सारणी V.11)। दक्षिणी क्षेत्र के बैंकों ने अपेक्षाकृत बेहतर आस्ति गुणवत्ता और वसूली प्रदर्शन द्वारा समर्थित उच्च लाभ की सूचना दी, जबकि उत्तरी क्षेत्र के बैंकों ने हानि दर्ज की।

4.2.2. प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

V.59. मार्च 2024 के अंत में, आठ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 609 पीसीएआरडीबी थे। वर्ष 2023-24 के दौरान पीसीएआरडीबी (संचित हानि का निवल) के समेकित तुलन पत्र का विस्तार हुआ, जिसका कारण आस्ति पक्ष में निवेश और अन्य आस्तियों में वृद्धि और देयताओं के पक्ष में जमा और अन्य देयताएँ रहीं (परिशिष्ट सारणी V.12)।

V.60. वर्ष 2023-24 के दौरान, पीसीएआरडीबी की समेकित आय में गिरावट आई, जो ब्याज आय में धीमी वृद्धि और अन्य आय में संकुचन को दर्शाती है। इसके विपरीत, उनके कुल व्यय में वृद्धि हुई, जिसके कारण परिचालन व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। नतीजतन, वर्ष के दौरान परिचालन लाभ कम हो गया (परिशिष्ट सारणी V.13)। उत्तरी क्षेत्र में पीसीएआरडीबी ने कुल हानि में 74.6 प्रतिशत का योगदान दिया, जबकि दक्षिणी क्षेत्र का लाभ में सबसे अधिक हिस्सा था।

V.61. पीएआरडीबी की आस्ति गुणवत्ता में वर्ष 2023-24 के दौरान सुधार हुआ, जिसमें जीएनपीए अनुपात एक वर्ष पहले के 39.7 प्रतिशत से घटकर 38.6 प्रतिशत हो गया (परिशिष्ट सारणी V.14)। उत्तरी क्षेत्र में पीसीएआरडीबी ने वर्ष 2023-24 के दौरान उच्चतम जीएनपीए अनुपात और सबसे कम मांग और वसूली अनुपात दर्ज करना जारी रखा। इसके विपरीत, दक्षिणी क्षेत्र ने सबसे कम जीएनपीए अनुपात और उच्चतम मांग और वसूली अनुपात बनाए रखा (परिशिष्ट सारणी V.15)।

5. समग्र मूल्यांकन

V.62. वर्ष 2024-25 के दौरान, यूसीबी ने उच्च पूंजी बफर, कम जीएनपीए अनुपात और बेहतर प्रावधान परिणामों के साथ अपने तुलन पत्र को मजबूत करना जारी रखा। अप्रैल 2025 से शहरी सहकारी बैंकों के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई फ्रेमवर्क की शुरूआत, चार-स्तरीय विनियामकीय संरचना और सुविचारित पर्यवेक्षी हस्तक्षेपों से जोखिम की प्रारंभिक

पहचान को सुदृढ़ करने और आश्वासन कार्यों को मजबूत किया जाना अपेक्षित है। यूसीबी के लिए एक छत्र संगठन, राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के परिचालन के साथ वित्तीय आघात-सहनीयता और मजबूत होने की उम्मीद है, जो अभिशासन को मजबूत करने, चलनिधि सुनिश्चित करने और क्षमता निर्माण और जोखिम प्रबंधन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है।

V.63. ग्रामीण सहकारी समितियों में, राज्य सहकारी बैंक और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दोनों बेहतर पूंजी पर्याप्तता और आस्ति गुणवत्ता के साथ लाभदायक बने रहे। हालांकि, दीर्घकालिक ऋण सहकारी समितियों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आगे देखें तो, सहकारी क्षेत्र के सतत विकास का समर्थन करने के लिए प्रौद्योगिकी अपनाना, व्यापार विविधीकरण और परिचालन दक्षता में सुधार करना महत्वपूर्ण होगा।